Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is one amendment by the Minister.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 1, *for* the word "Fifty-third" the word "Fifty-fourth" be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The House is adjourned for lunch up to 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-nine minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty three minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

Severe Drought Situation in Various Parts of the Country

THE DEPUTY CHAIRMAN : Whenever we discuss drought, there is always a drought in the House. It is a tragic situation. I think we should stop discussing drought, only then we might have some rains.

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैडम, कल से बारिश हो रही है ।

उपसभापति: जी, जब एक्सेप्ट किया था तो बारिश नहीं हो रही थी । एक्सेप्ट करके बारिश हो रही है । अगर डिसकस न करें तो हमें क्या एतराज है ! सुरेश जी, बोलिए ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मौसम विभाग और कृषि मंत्री जी और यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारे देश का वर्ष 2002 का जो सूखा है, वह दरअसल अभी तक का सबसे भयंकर और भयावह सूखा है । हमारे देश में लगभग 15 राज्य ऐसे हैं और लगभग 375 जिले ऐसे हैं जो सूखा से प्रभावित हैं । स्वयं कृषि मंत्री जी ने माननीय सदन में 22 नवंबर, 2002 को यह स्वीकार किया है कि 15 राज्य सूखे से जबरदस्त प्रभावित हैं । अगर इसके कारणों को देखा जाए तो वर्षा इसका प्रमुख कारण हैं, लेकिन जल-संचय, जल का सही प्रबंधन न होना, रैन वाटर हारवेस्टिंग के बारे में सही कदम न उठाना और वाटर एक्सप्लाएटेशन को न रोका जाना, यह सारे भी कारण हैं । लगभग 19 प्रतिशत वर्षा में कमी रही और उसके कारण हमारे देश का लगभग 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ । 110 मिलियन हैक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित होने की वजह से कृषि योग्य नहीं रह पाई और इससे किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई । यह सोचा जा सकता है कि इस देश में 60 प्रतिशत किसानों की दशा जब दयनीय हो जाए तो देश की दशा दयनीय होनी स्वाभाविक है और देश की दशा, महोदया, जब दयनीय हो जाए तो हम गर्व से नहीं कह सकते कि "हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ।"

महोदया, जहां पानी की कमी है, आपने आते ही सही फरमाया था और यह सही है कि जब सूखे की चर्चा होती है तो आप उस महान आसंदी पर विराजमान रहती हैं, कृषि मंत्री वही रहते हैं जहां सामने बैठे हुए हैं और इस डिबेट को शुरु करने वाले भी वहीं रहते हैं जहां आज बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तर वही का वही रहता है, नतीजा वही का वही रहता है, मर्ज वही का वही रहता है, मरीज वहीं के वहीं रहते हैं, निदान और उपाय कुछ नहीं निकल पाते हैं सिवाय आश्वासन और वचनों के ।

महोदया, मैं अपनी बात प्रधान मंत्री जी के 18 दिसम्बर, 2002 को इस सदन में दिए गए वक्तव्य से प्रारम्भ करना चाहता हूं क्योंकि जब भी सदन में चर्चा होती है, चाहे सूखे पर होती है या बाढ़ पर होती है, हम न तो कोई दीर्घकालिक उपाय निकाल पाते हैं, न कोई नीति निर्धारित कर पाते हैं, केवल चर्चा करते हैं और इस औपधारिकता की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन जो वक्तव्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया, वहां से मैं एक नई शुरुआत इस चर्चा की प्रारम्भ करना चाहता हूं ताकि यह केवल औपचारिकता ही न रह जाए, इस विडम्बना में ही हम न फंसे रह जाएं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं, बिन्दु क्रमांक 3 में कि :-

> "सूखे से निबटने के लिए 555 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी जिसे या तो आपदा राहत कोष अथवा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक राहत कोष से वहन किया जाएगा।"

प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि :-

> "खाद्यान्न विपुल मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा, जितनी मांग की जाएगी । यह खाद्यान्न तीन महीने अर्थात् जनवरी, 2003 तक के लिए है । तत्पश्चात् अधिक खाद्यान्न जरूरतमंद राज्यो को उपलब्ध कराया जाएगा । निःसंदेह राज्य सरकारें आबंटित खाद्यान्न के इस्तेमाल के बाद अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर सकती हैं ।"

महोदया, मेरे पास तीन मुख्य मंत्रियों के पत्र हैं--मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री का। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 24 जुलाई, 2002 को 2.5 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी और 819.62 करोड़ रुपए राशि की मांग की थी जो मत्स्यपालन की क्षति के अलावा थी । इस के अलावा जो एक केन्द्रीय दल की टीम गई थी, उसके समक्ष जो मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया, उसमें 315.79 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी, साथ ही 2.56 लाख मीट्रिक टन की बात कही गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस संबंध में एक पत्र 3 जनवरी, 2003 को लिखा था जिसमें कई राज्यों में सूखे से व्याप्त स्थिति से निबटने के लिए उन्होंने कुछ कदम सुझाए थे कि जिन राज्यों में सूखा पड़ने की संभावना है, वहां कम से कम 50 प्रतिशत की राशि और खाद्यान्न पहले से दें दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए और जो पार्ट्स हैं देने के, सैंट्रल रिलीफ कमिशनर को दे दिए जाएं और साथ ही जो ऐलोकेशन है, उसके मामले में ज्यादा औपचारिकताएं न बरतकर नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए उसकी पूर्ति की जाए, जिसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने 11 फरवरी को दिया और राजस्थान से संबंधित जो बात कही, निश्चित रूप से वह गुमराह करने की बात थी, जिसका उत्तर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने 12 फरवरी को दिया और 75 प्रतिशत लोगों के लिए, जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए 10 दिन के लिए 5 रुपए प्रति किलो की बात थी, उस नीति का उन्होंने विरोध किया और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी ने भी यह कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा प्रति माह मजदूर को केवल दस दिन कार्य के लिए जो पैसा दिया जाना है उसे आवश्यक बताया गया है, जबकि सूखे से प्रभावित लोग केवल दस दिन ही खाना नहीं खाएंगे और बाकी 20 दिन के लिए उनकी कैसे व्यवस्था होगी, यह सोचने की बात है । इसलिए न केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बल्कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने यह व्यथा व्यक्त करते हुए कहा है कि कृषि मंत्रालय का यह जो निर्णय है, वह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अगर एक परिवार में पांच या छह लोग रहते हैं तो केवल दस दिन की मजदूरी करके वे पूरे महीने के भोजन की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं । इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने 3.5 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन करने की बात कही है । इसी प्रकार की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी कही है । मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 31,002.45 करोड़ रुपए मांगे गए हैं जिनमें से केवल 1,999.14 करोड़ रुपए प्रदान किए गए जो हाई लेवल की कमेटी ने दिए । आखिर इन पेचीदगियों से हटकर जितना नुकसान हुआ है, कम से कम उसका 50 प्रतिशत आवंटन तो किया जाना चाहिए, साथ ही SGRY योजना के तहत भी आवंटन किया जाना चाहिए । मैं यह जानना चाहूंगा कि SGRY योजना के अंतर्गत सूखे से प्रभावित राज्यों में कितनी मांग की गई थी और उनको कितनी राशि दी गई ? यदि माननीय मंत्री महोदय इसका ब्योरा दे सकेंगे तो मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 18 दिसंबर, 2002 को जो वक्तव्य इस सदन में दिया है, यह उसकी आपूर्ति की दिशा में उठाया गया कदम होगा ।

महोदया, जहां तक कृषि मंत्री जी की निष्ठा का प्रश्न है, उस पर मैं कोई शंका व्यक्त नहीं करना चाहता हूं । मैं उनकी पहल पर विश्वास करता हूं लेकिन जो कदम उठाए जाने चाहिए वे इतनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं कि समय पर वे कदम उठाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जहां तक कृषकों से संबंधित कदम उठाए जाने की बात है, कृषि नीति से संबंधित कदम उठाए जाने की बात है, सूखे से निपटने संबंधी कदम उठाए जाने की बात है, उसके बारे में निश्चित रूप से हमें वरीयता के आधार पर कदम उठाने चाहिए क्योंकि यह प्रश्न पूरे देश का है।

जब हम किसी समस्या के बारे में यहां जिक्र करते हैं तो वह समस्या एक या दो प्रतिशत लोगों को प्रभावित करती है लेकिन सूखे से उत्पन्न समस्या निश्चित रूप से पूरे देश के करीब 5 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रही है । वे लोग न केवल पीने के पानी से वंचित रह जाते हैं, न केवल कृषि के लिए सिंचित सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, बल्कि सूखा पड़ने की वजह से उन्हें कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है । जब मैं सामाजिक समस्या का जिक्र करता हूं तो माननीय जनेश्वर मिश्र जी यहां मौजूद हैं, इन्होंने जिक्र किया था कि जब सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, जब आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है तो इसका सबसे ज्यादा शिकार न केवल गरीब किसान होता है, बल्कि महिलाएं भी होती हैं और जब महिलाएं इसका शिकार होती हैं तो किस प्रकार से उनका शोषण होता है, इसकी व्याख्या करना एक हृदय-विदारक घटना होगी, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए निश्चित रूप से हमे प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा विचार है ।

महोदया, सूखे से जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं और उससे कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं । जब पैदावार कम होती है तो देश की आय भी कम होती है । इससे किसान को तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है लेकिन देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है । देश की जो मानसिक स्थिति है, जब मैं मानसिक स्थिति कहता हूं तो निश्चित रूप से जब देशवासियो की शारीरिक अवस्था ठीक नही होगी तो उसका प्रभाव यहां के लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा ।

इसलिए सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन, दोनो प्रकार की नीतियां बनाए जाने की जरूरत है । मैं सोचता हूं कि इस पर विचार करने से हम लोग निश्चित रूप से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे । एक विडंबना यह है कि हमारे देश मे लगभग 4 प्रतिशत भूमि ही नहरो से सींची जाती है । स्थिति यह है कि हमारे यहां का जल स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है । इसकी वजह यह है कि जो हमारे परंपरागत साधन थे, जैसे गांवो मे एक समय मे कुएं और बावड़ियां हुआ करती थी, जल का संचय होता था, गांवों मे तालाब हुआ करते थे, उन तालाबो का पानी न केवल मवेशियो के पीने के उपयोग मे आता था, बल्कि आम इंसान की भी अन्य जरूरतो जैसे नहाना, कपड़े धोना आदि के काम मे आया करता था, आज उन परंपरागत विधियो से हम दूर हो गए हैं । बल्कि एक एयरकंडीशंड रूम मे बैठ कर ऐसे नीतिकार इस निर्णय को कर रहे हैं। मैं उनकी नीति पर शंका नही कर रहा हूं लेकिन चूंकि अनुभव की कमी है इसलिए हम किसानो के दर्द का अहसास नही कर सकते हैं, किसानों की परेशानी का अहसास नहीं कर सकते हैं। महोदया, मैं चूंकि किसान परिवार से आया हूं इसलिए कह सकता हूं कि आगे जब सूखा पड़े तो किस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। किसानो को जहां यह बताया जाए कि यदि जिन जगहो पर मौसम विभाग यह घोषणा करता है कि यहां सूखा पड़ सकता है तो पहले से किसानो को यह बताए जाने की आवश्यकता है कि यदि आपको सोयाबीन बोना है और यहां यदि सूखा पड़ेगा तो अब सोयाबीन बोने की आवश्यकता नही है, बल्कि अन्य कोई बीज बोने की आवश्यकता है ताकि आपकी खेती प्रभावित न हो। यदि हम इस प्रकार के कदम उठाएंगे तो किसान भारी नुकसान से बच सकता है, इसके बारे में भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। न केवल हम सूखा संहिता बनाएं बल्कि मौसम संहिता भी बनाया जाना जरूरी है। मौसम विभाग के पास ऐसे आधुनिक उपकरण होने चाहिए जो यह बता सकें

कि किन-किन स्थानों में कब-कब मौसम की क्या-क्या स्थिति जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है। वाटर का जो एक्सप्लॉएटेशन है उसको रोकने की बात है। यह जो ग्राउंड वाटर है उसके संचय करने की बात है। इस दिशा में गांव के नौजवानों को लगाए जाने की जरूरत है। महोदया, ऐसा मेरा विचार है। इसके लिए हमारे जो कृषि और जल वैज्ञानिक हैं इनको निश्चित रूप से मिलजुल कर सूखा और बाढ़ दोनों की स्थिति से निबटने के लिए न केवल महत्वाकांक्षी योजनाएं बनानी चाहिएं बल्कि उन योजनाओं को बनाकर देश के सामने और देश के किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना बहुत ज्यादा जरूरी है।

महोदया, मैं अपने राज्य की बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अन्य सदस्यों को भी बोलना है। मैं जिस प्रदेश -मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं उसके जो 33 जिले हैं उनकी 195 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं। इसके लिए जो एक अध्ययन दल गया वह जांच भी करके आया। महोदया, जैसा मैंने कहा कि पिछले समय जब सूखे पर चर्चा हो रही थी तो माननीय मंत्री महोदय ही थे कृषि मंत्री के रूप में और बड़ी आशा से हमने उनसे कुछ गुजारिश की थी और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि जहां तक मध्य प्रदेश का ताल्लुक है उसे किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन मैं उनसे फिर विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने जो मांग की है खाद्यान्न के बारे में, मध्य प्रदेश ने जो वित्तीय मदद की मांग की है चाहे राष्ट्रीय आपदा राशि के रूप में या अन्य रूप में, कृपापूर्वक उस राशि को उपलब्ध कराएं। ऐसा न हो कि कहीं यह भावना जाए कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण या सौतेलापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और छीन-छीन कर अपने-अपने लोगों को देने की एक प्रेक्टिस एडाप्ट की जा रही है। दूसरों को दें उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, वह भी उसी प्रकार के पात्र हैं जिस प्रकर का पात्र मध्य पदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्य हैं लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जहां सूखा बहुत ज्यादा पड़ा है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मध्य प्रदेश में बहुत-बहुत भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, पंजाब में भी यही स्थिति है। राजस्थान की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में तो पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जब सूखे की चर्चा होती है तो राजस्थान अव्वल दर्जे पर होता है। इसलिए ऐसे राज्यों को आइडेंटिफाइ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां लगातार सूखा पड़ता है वहां के लिए निश्चित रूप से अन्य राज्यों से हट कर योजनाएं बनाना चाहिए, अन्य राज्यों से हटकर कोई कदम उठाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभापति महोदया, देश के विभिन्न भागों में बार-बार प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी चक्रवात आ जाता है, कभी भूचाल आ जाता है। कभी स्थिति ऐसी विषम भी होती है कि कभी बाढ़ भी आती है और सूखा भी रहता है। इस परिस्थिति की बार-बार हम यहां पर सदन में चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार की जो परिस्थिति है वह विशेष रूप से चिंताजनक इसलिए है कि जो राज्य कभी भी सूखे की चपेट में नहीं आते थे वह राज्य भी -पंजाब जैसा राज्य, हरियाणा जैसा राज्य आज इस बार सूखे की चपेट में हैं। देश के कुल 549 जिलों में से 333 जिले सूखे से प्रभावित हैं। अनावृष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो पिछले 12 सालों में बारिश की उतनी कमी कभी नहीं रही

जितनी कि इस साल पूरे देश में रही है। इस अकाल की परिस्थिति के कारण, सूखे की परिस्थिति के कारण देश में कृषि की पैदावार तो घटती ही है, कम होती ही है और इसका कृषि की उत्पादकता पर भी विपरीत असर होता है। सूखे के कारण कृषि की उत्पादकता घटती है। देश में पानी की कमी के कारण बिजली का उत्पादन कम होता है लेकिन किसानों के द्वारा बिजली की मांग बढ़ जाती है, देश में पीने के पानी की समस्या हो जाती है, देश में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, देश में पशु-धन के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके कारण राजस्थान में जैसे हजारों की तादाद में पशुओं की मौत हुई है, ऐसी परिस्थिति देश में बार-बार निर्माण होती है।

आज हमारे समक्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम देखते हैं कि इसका सीधा असर हमारे कुल सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है और उसके कारण देश के उद्योग-धंधे, व्यापार में लोगों की आय कम होती है, लोगों की क्रय-शक्ति कम होती है और इसके कारण लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।

इस वर्ष की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने सूखे से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स माननीय उपप्रधान मंत्री जी अध्यक्षता में बनाई है। इस टास्क फोर्स के द्वारा पूरे देश में पानी के व्यवस्थापन की बात सोची जा रही है, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराये जाएं, यह बात भी सोची जा रही है। सूखे से पीड़ित राज्यों के नागरिकों को, पशु-धन को कैसे राहत पहुंचाई जाए, यह बात भी सोची जा रही है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के जो काम चलें उसमें से कायमी दृष्टि से मिल्कियतों का सृजन कैसे हो, वैसा भी एक मुद्दा इस टास्क फोर्स के सामने विचाराधीन है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

उपसभापति महोदया, देश में 16 प्रतिशत भौगोलिक विस्तार ऐसा है जो कायमी दृष्टि से सूखे से प्रभावित है। देश की 11 प्रतिशत आबादी और 19 प्रतिशत जिले ऐसे हैं जो कायमी दृष्टि से सूखे से प्रभावित हैं। इस विस्तार की दृष्टि से हम सोचें। मैं गुजरात प्रदेश से आता हूं और उसकी परिस्थिति अन्य राज्यों से विचित्र है, चिन्ताजनक है। गुजरात की 27 प्रतिशत आबादी और 43 प्रतिशत विस्तार सूखे से कायमी दृष्टि से प्रभावित है। गुजरात के कुल जिलों में से 60 प्रतिशत जिले ऐसे हैं जो सूखे से कायमी दृष्टि से प्रभावित हैं। गुजरात के पास सबसे बड़ा लम्बा समुद्र का किनारा है। हमारे यहां नर्मदा, ताप्ती और मही जैसी पानी से भरपूर नदियां हैं। हमारे पास समृद्ध बंदरगाहों की श्रृंखला है, खाड़ी ऐसी है जिससे बंदरगाहों का काम चल सकता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो देश में दूसरे नम्बर पर गुजरात का स्थान है। फिर भी, पिछले पांच साल की लगातार प्राकृतिक आपदाओं को हम देखेंगे तो 1997 में भयंकर बाढ़ आई। वर्ष 1998 और 1999 में सूखा पड़ गया, चक्रवात भी आ गया। वर्ष 2000-01 के साल में कम या ज्यादा मात्रा में सूखा पड़ा और 2001 के साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा व्यापक असर देने वाला भूकम्प, भूचाल आ गया और इसके कारण गुजरात की पूरी अर्थव्यवस्था पिछले पांच साल में चरमरा गई है। गुजरात की प्राकृतिक परिस्थिति ऐसी है कि 66 प्रतिशत गुजरात का जो विस्तार है वह पत्थर वाली जमीन का विस्तार है, खड़ग वाली जमीन का विस्तार है। चार प्रतिशत विस्तार ऐसा है जहां पर समुद्र का बहाव आगे आ गया है इसके कारण सिर्फ 30 प्रतिशत जमीन का विस्तार ऐसा है जहां पर जमीन में पानी जा सकता है और यही कारण है कि हमें गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश के पानी पर आश्रित होकर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सोचना पड़ता है, गुजरात की खेती के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था का विचार करना पड़ता है । आज

गुजरात में 124 लाख एकड़ जमीन खेती के लायक है, उसमें से सिर्फ 30 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था है । नर्मदा बांध बनने के बाद, नर्मदा का पानी गुजरात में आने के बाद भी सिंचाई की व्यवस्था 45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी । 55 प्रतिशत खेती के लायक जमीन पर सिर्फ बारिश का पानी आए, तभी खेती हो सकती है । इस दृष्टि से गुजरात में दूसरी सिंचाई की योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के संबंध में हमें विचार करना पड़ेगा। गुजरात में पिछले पचास सालों में 20 साल सूखे के, अकाल के आए हैं । गुजरात में, मैं जिक्र कर रहा था, पिछले पांच सालों का । 1999-2000 में 9,449 गांव सूखे से प्रभावित थे, 2000-2001 में 15,148 गांव सूखे से प्रभावित थे । 1998 में साइक्लोन आया था, 1999 में साइक्लोन और सूखा दोनों साथ में आए । 1997 में गुजरात की सरकार को 664 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े । 1998 में 2100 करोड़ रुपये साइक्लोन से निपटने के लिए खर्च करने पड़े । 1999 में साइक्लोन के लिए 95 करोड़ और सूखे के लिए 585 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। 2000-2001 में 820 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च करने पड़े।इस बार की स्थिति चिंताजनक इसलिए है कि 2002-2003 के इस साल में गुजरात के 5,589 गांव और 55 शहर ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की गंभीर समस्या है । 4,529 गांवों में गुजरात की सरकार ने अधिकृत रूप से यह घोषणा कर दी है कि ये सूखे से प्रभावित विस्तार क्षेत्र हैं। जिस जमीन पर खेती होती है उसमें से इस साल करीब 10 लाख हैक्टेयर जमीन पर पानी के अभाव के कारण बुवाई नहीं हो सकी । गुजरात को पिछले पांच सालों में लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि के उत्पादों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान भुगतना पड़ा है । परिस्थिति विकट इसलिए है कि आज पानी की समस्या है, पीने के पानी के लिए खर्च करना पड़ रहा है - 1982 से 1992 तक के दस साल में पीने के पानी के लिए योजना बनी थी । 1981-82 में सिर्फ 3 हजार 350 के करीब गांव ऐसे थे जहां पर पीने के पानी की समस्या थी । लेकिन 1990 आते आते 2000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद 900 विलेजिज़ की संख्या बढ़कर 13 हजार के करीब पहुंच गयी । यह परिस्थिति इसलिए है कि बारिश की कमी है । हमारे कच्छ का जो इलाका है, वह सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका इस साल भी है । वहां पर पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी 266.68 मिलियन क्यूबिक मीटर है, वहां पर आज सिर्फ 6.72 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही है यानी स्टोरेज कैपेसिटी का 2.52 प्रतिशत । सौराष्ट्र के इलाके में 2,325 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रह क्षमता की तुलना में 425 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है यानी सिर्फ 18 प्रतिशत । उत्तर गुजरात में 627.28 मिलियन क्यूबिक मीटर संग्रह की क्षमता की तुलना में सिर्फ 16.5 प्रतिशत स्टोरेज है लेकिन सिर्फ 2.56 प्रतिशत स्टोरेज हुई है । इसके कारण लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या है । इसके अतिरिक्त वहां पर फ्लोराइट वाला पानी मिलता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर ऐसे पानी के कारण लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल गयी हैं। यह परिस्थिति भी चिंताजनक है । इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति चिंताजनक इसलिए है कि वहां पर एक ओर 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान यह हुआ और पिछले पांच साल में सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एस. में से जो भी राशि गुज़रात को मिली, उसके उपरांत 4,731 करोड़ 55 लाख का खर्च इन प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में गुजरात को करना पड़ा है । महोदया, इस बार 2002-03 की जो परिस्थिति है, गुजरात की सरकार ने उसका आकलन किया है और वह केन्द्रीय मंत्रालय को भेजा भी है । 895 करोड़ 34 लाख रुपए की उन लोगों ने अपेक्षा रखी है । पीने के पानी के लिए पैसा चाहिए, रोज़गार के लिए पैसा चाहिए, पशु-धन के चारे के लिए पैसा चाहिए, बीमारियों को झेलने के लिए पैसा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए । लेकिन आज परिस्थिति यह है

3.00 p.m.

कि गुजरात को सी.आर.एफ.(कैलेमिटी रिलीफ फंड) में से जो पैसा मिल रहा है, वह सिर्फ 133.46 करोड़ ही मिलेगा । बाकी जो पैसा है, उसके लिए गुजरात की अर्थव्यवस्था पर उसका भार आएगा। मेरा यह सुझाव रहेगा कि 133.46 करोड़ रुपए की राशि जो भारत सरकार को देनी है, वह अविलम्ब एक ही हफ्ते में दे दे । 2003-04 के लिए गुजरात का सी.आर.एफ. में से जो हिस्सा रहेगा, वह 186.46 करोड़ का रहेगा । मेरा भारत सरकार को यह सुझाव रहेगा कि 2003-04 की जो यह राशि हमको मिलनी है, उसमें से भी अगर एक या दो किश्त दो हफ्ते में हमको दे दी जाए तो वह पूरा किया जा सकता है ।

एक बार ऐसी परिस्थिति हुई थी और केन्द्र सरकार ने वेजेज़ एंड मीन्स में से ऐडवांसेज देकर गुजरात की मुश्किलात में मदद की थी । मेरा यह सुझाव रहेगा कि अगर 300 करोड़ की राशि वेजेज़ एंड मीन्स ऐडवांसेज में से गुजरात को दी जाए तो गुजरात को जो भी खर्च प्राकृतिक विपदाओं को झेलने के लिए करना पड़ रहा है, उसमें उनको सहायता मिलेगी ।

आज हम आभारी हैं कि रेल मंत्रालय ने गुजरात को चारा ढोने के लिए वैगन उपलब्ध कराए हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं । हमको प्रतिदिन दो वैगन चाहिए जिससे कि कच्छ के ज़िले में, उत्तर गुजरात के ज़िले में, बनासकांठा, सौराष्ट्र के ज़िलों में वह चारा हम ले जा सकें । मेरा रेल मंत्रालय से भी यह निवेदन रहेगा कि प्रतिदिन के दो वैगन गुजरात की सरकार को उपलब्ध कराएं । जो शहर सूखे के क्षेत्र में नहीं आते हैं, जो सूखा घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन 55 शहर ऐसे हैं जहां पीने के पानी की तीव्रतम समस्या है, तो मैं यह चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी के राहत कोष से अगर 17 करोड़ रुपया इसके लिए उपलब्ध कराया जाए तो गुजरात को बहुत सहायता मिलेगी ।

पचौरी जी ने जो सुझाव दिया, मैं अब उस पर आना चाहूंगा । देश में जो हमारी 700 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है, उसके सामने हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 179.73 बिलियन क्यूबिक मीटर है । 75.42 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता के लिए हमारा काम चल रहा है । 132.32 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के लिए हम नई योजनाएं बना रहे हैं । इन सबका अगर हम मेल बैठाएं तो 387.47 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की व्यवस्था हम कर पा रहे हैं । बाकी 302.53 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आज भी समुद्र में बहता चला जा रहा है । इसको रोकने के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी और इसके कारण जो हमारी प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता है, वह आवश्यकता हम पूरी कर पाएंगे ।

मेरा एक दूसरा सुझाव भारत सरकार को यह भी रहेगा कि नर्मदा बांध की ऊंचाई 110 मीटर तक ले जाने के लिए जो भी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, उन सबको समाप्त किया जाए । मेधा पाटेकर और उनकी मंडली के द्वारा अनेक आंदोलनकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । उन सबको समाप्त करने की दृष्टि से हमें सोचना होगा । नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा जो भी आवश्यकताएं हैं, वे आवश्यकताएं गुजरात सरकार पूरी कर रही है। आज 98 मीटर पर उस बांध का काम रुका हुआ है, उसे आगे ले जाने की दृष्टि से भी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी मंजूरी दे दे तो हमारे यहां यह काम हो सकता है ।

हमारे महामहिम राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी असम के दौरे पर गए थे । उस दौरे का एक प्रसंग उन्होंने अपनी पुस्तक "इग्नाइटेड माइंड्ज़" में उद्धृत किया है । मैं उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा कि वहां तेजपुर की एक शाला में एक विद्यार्थी ने हमारे राष्ट्रपति जी

से एक सवाल पूछा । ब्रह्मपुत्र नदी मे बार- बार बाढ़ आती है तो क्यों यह ब्रह्मपुत्र का पानी तमिलनाडु मे नही ले जाया जा सकता? यह ब्रह्मपुत्र नदी का पानी राजस्थान में क्यों नहीं ले जाया जा सकता? राष्ट्रपति जी ने तो उस बच्चे को ऐसा जवाब नहीं दिया। कि पानी राज्यों का विषय रहता है। पानी के लिए राज्य झगड़ते हैं, पानी का बंटवारा करने के लिए राज्यों में विवाद चलता है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने जो जवाब दिया, वह जवाब यह है कि देश के पानी के संसाधनों के लिए, देश के विविध राज्यों की नदियों को जोड़ने के लिए युवाओं को भगीरथ कार्य करना पड़ेगा। भारत की सरकार ने यह कार्य आज अपने हाथ में लिया है। देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है। पांच लाख साठ हजार करोड़ की लागत से दो हजार सौलह का साल आने तक, देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। महोदय, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि 1978 में जब इस देश मे मुरारजीभाई देसाई प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस वक्त उत्तर की नदियों और दक्षिण की नदियों की नहर बनाने की योजना बनी थी। उस वक्त डा. दस्तूर ने यह कहा था कि एक बार ये नहरें बन जाएं तो नहर माला के आधार पर पूरे देश का पानी एक विस्तार से दूसरे विस्तार मे ले जाएंगे। इसमें कोई बीस साल का समय लगेगा। उस वक्त का यह विचार अगर क्रियान्वित हो गया होता तो आज 2002 में हमें भीषण अकाल की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता । मैं चाहता हूं कि नदियों को जोड़ने की जो भागीरथ योजना बनी है, भारत सरकार समय से पहले इसके लिए कार्यशील हो जाए और जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दे। आज इस परिस्थिति पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri C. Ramachandraiah. Even those people from your Party who were fighting for this discussion are not there.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): They are waiting for my turn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are they waiting for you to bring the water?...*(Interruptions)*.. Three of them are there. ...*(Interruptions)*.. They all are sitting together. ...*(Interruptions)*..

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Madam, I thank you in the first instance for your accepting my request to allow us to raise a discussion on the floor of the House on the drought situation in the country. Madam, in spite five decades of irrigation development, in spite of our completion of Nine Five Year Plans, in spite of spending lakhs of crores of rupees on rural development and irrigation sector, in spite of our having a very high scientific pool among the comity of nations and high technological advancement and in spite of our achievement of the Green Revolution which made us to be self-sufficient country in the matter of foodgrains, still we have been talking about drought. It is a very unfortunate thing. We are not able to change the condition of the farmers in rural areas in this country.

Drought as such seems to be an inevitable thing for this country. It is a common phenomenon. I read an article written by Shri Mohan Dharia, an eminent socialist which says, "In spite of completion of all the projects and exploring all the hydraulic systems that are available in this country, we can irrigate only 50 per cent of the sown soil in this country. Monsoon can and will fail. But it is a drought of action that aggravates the situation." Madam, it is not only drought but it is drought on the part of the Government that aggravates the situation because a number of times we have been discussing and ultimately the request to the Government is that the impact of this drought has to be minimised. We have become self-sufficient at macro-level. We have got 60 million tonnes of foodgrains in our godowns. We have got a very moderate rate of inflation. We have huge foreign exchange reserves. But, in spite of all these things, still, a major chunk of the population is living Below the Poverty Line. The economy of this country has been developed in such a way that it does not have that resilience to withstand the impact of drought consecutively for three to four years. Still, starvation deaths are reported in Rajasthan and in other parts of the country. Unemployment is there. In spite of the availability of huge quantity of foodgrains, still, a major percentage of people cannot afford to buy foodgrains. Affordability is not there. So, the primary duty of this Government or any civilized Government is to provide food to the people. I have to quote Swamy Paramahamsa. He says, "There is no religion with empty stomach. The religion lies where you feed the people of this country." This dichotomy has to be addressed. These anomalies have to be redressed. I appeal to the Government to rise to the occasion. Madam, till today, the Government does not have and could not build up the machinery to foresee the natural disasters like drought, failure of monsoons, floods and prepare a contingency plan as to how to overcome this. The Government has yet to build up that machinery. It has got a cascading effect. The drought affects your savings. It affects the investment. It affects the manufacturing sector. The Government has got a very embolden claim of achieving the growth rate of 8 per cent, particularly in the first year of the Tenth Five Year Plan. It is going to be over by this March. The Central Statistical Organisation has estimated a growth rate of 4.4 per cent for the first year. So, this drought, particularly during the last two years, affected the growth rate of this country to the extent of 2 per cent. I want to emphasise here the impact of drought on the economy of this country. In this connection, I would like to give some suggestions.

Madam, as far as my State is concerned, the condition is very pathetic and grim. The total agricultural loss in my State is around Rs.5,300 crores. The deficiency in rainfall is 32 per cent. This has been recorded throughout the State and the entire State has been declared as drought-affected, including Hyderabad city which is reeling under drought due to non-availability of water. The Centre has released five lakh tonnes of rice to provide employment. It is not sufficient. We have requested the Government of India for a cash relief of Rs. 2,373 crores. Out of which, the Task Force has announced Rs. 174.61 crores. Of these Rs. 174 crores, not even a single paisa has been released till today. The sanctioned amount has not been released so far. In spite of the visits of the two Central Teams, the Government has not risen up to the occasion. I should say that it has got a very lukewarm attitude towards our State. The conditions of the farmers are so pathetic in our State that they are selling their cattle to the slaughterhouses for their sustenance and livelihood and many of them are leaving the villages. There is a mass exodus from the State to other affluent parts of the country. Such migrations are creating problems in cities as well. I am sorry to point out here that a meagre amount released from the Calamity Relief Fund is not sufficient even to meet the fraction of the requirement of the State. The drought situation demands that even drinking water supply may have to be arranged for many rural areas through transportation. Fodder has to be provided for cattle, in addition to rice under the Food-for-Work Programme for the rural poor.

So, I want to make some suggestions in this regard. You have to step up the investment in the agricultural sector, especially in irrigation. And, if I quote the report of the Planning Commission, the investment in irrigation sector was 23 per cent in the First Five Year Plan. Now, in the Ninth Five Year Plan, it has been reduced to 7 per cent. Clearly, it has been reduced considerably. Till now, we could provide irrigation to only 39 per cent of the sown area. The Tenth Plan has got a spill over of 159 major and 242 medium irrigation projects; while, the allocation for irrigation and agriculture, in the Tenth Five Year Plan, is considerably low. Some time back, I heard the hon. Minister, while he was addressing a Press conference, saying that allocation to the agriculture sector in the Tenth Plan has considerably reduced. I don't know -- this being an agrarian economy, which has got a tremendous impact on the overall development of the country -- how the Government will achieve 8 per cent growth because the contributing factor to the overall GDP is much from the agricultural sector. As a permanent measure, I am very happy, the Government has constituted

a task force for linkage of rivers in this country, which has been pending for a long time. But, I have got my own apprehensions about this. Can you initiate efforts to arrive at a political consensus in order to get a clearance for this project because 'water' is now in the Concurrent List? Without the consent of the States, it would be very difficult to complete this project. In fact, this project is a mission, which can be spread over 40-50 years, with an investment of Rs. 6 lakh crores. Unless 'water' is declared as a national asset, it is very difficult to complete this project. Can you initiate measures to interact with the Chief Ministers of various States, which are being represented by various political parties, so that a consensus can be arrived at? We have been unable to solve the inter-State water disputes. Tamil Nadu has got a row with Karnataka, so far as Cauvery is concerned. So, all these problems have to be solved. The Government of India has not been successful in solving these problems. So, a machinery has to be created, and a national consensus has to be arrived at. Now, after 73rd and 74th amendments of the Constitutions, even the Corporations, Municipalities and *Panchayats* are involved in water management. So, this aspect has also to be taken into account, and a consensus has to be arrived at. I want to point out one more thing to the Government of India -- why do you distrust the States? States have got their own obligations towards their people. States have got a correct mechanism. How can 2-3 Secretaries and Joint Secretaries, by visiting for half-a-day or one day, assess the net damage that has been done to the States? It is very surprising to me that the same officers, who had once served the States, and had sent the reports regarding the requirements of the States, when they come to the Centre and visit those States, have different perceptions. *(Interruptions)* Please trust the State Governments. State Governments have also got obligations to their people. They know how to assess the damage that has been done to the people. Of course, the Government of India may have constraints because their deficit is much more than the States; and, they have to contain the fiscal deficit of the country. Your fiscal deficit is 24 per cent, whereas ours is not even 7 per cent. So, what I am trying to say is, it is a federal country; it is a Union of States. How long can you mistrust the States? You have to trust them. You send your team, but they submit their reports at their pleasure. Here, I would like to cite one example. When Mr. Liyaqat Ali Khan was the Prime Minister of Pakistan, there was an acute famine in Pakistan.

There was a famine in the country and the concerned file had come to him. The Secretary kept the file and was waiting for rehabilitation

measures to be initiated. He kept the file pending saying, "you put it up tomorrow." It was going on. When the floods came, he thought that it was high time to initiate rehabilitation measures for flood victims. And then, the measures for flood relief were recommended. Let us not repeat that performance here. You should rise to the occasion because the States are suffering a lot. You should believe the States. There should be a perfect coordination between the Centre and the States in formulating the schemes for employment generation, and providing succour and relief to the victims of the natural calamities, because the States have got the machinery to provide all these things. The Government of India has to respond to the needs of the States. My friend is sitting here, I don't know whether I can refer to Karnataka or not. We had requested the Chief Minister of Karnataka, "you have got surplus water, you don't need it, so, kindly release that water. We are prepared to provide electricity that will be generated by this." We wrote a letter to the hon. Prime Minister also. And the hon. Prime Minister has not responded to it. This is a very pathetic situation. As far as my knowledge goes, in the span of the last hundred years, not even once has the so-called KCA canal in my district failed to provide water to farmers. It was constructed by Sir Arthur Cotton. Not even in a single year has it failed to provide water to farmers. But, now the situation is so pathetic that farmers are selling their cattle. There is a mass exodus of people from rural areas to other affluent areas of the country. Ours is a civilized Government. Our Chief Minister had written a number of letters to the Karnataka Government and to the hon. Prime Minister to come to our rescue. But never have they come to our rescue. In spite of all our requests, not even a single paisa has been released till date. Everybody, every political party, feels that we have been taking more advantage of the Government, which is not the case. I want to make this point clear. It is not the case at all. ...*(Interruptions)*... I am saying this from records. ...*(Interruptions)*...I am showing the record. ...*(Interruptions)*...We want to keep the Government in a stable manner. ...*(Interruptions)*...We are not destabilizers. We want to keep a stabilized Government here, despite all these odds. ...*(Interruptions)*... To sum up, I request the Government to rise to the occasion and help the States to face this unprecedented situation.

There is one more point which I want to bring to the notice of the Government. Why don't you prepare the society to face these natural calamities? In developed countries, you don't hear of any drought. Why don't you prepare the society for it? You are always complacent. Whenever a natural calamity strikes, you wake up and come to the rescue

of the people, and by that time the rescue work gets delayed. So, people have developed a philosophy, 'it is our *'Karma'* and we have to bear the brunt of it.' The Government never tries to initiate appropriate measures, never tries to foresee the future. I think, Mr. A.K. Roy predicted drought four years back. I read it in the newspapers. Kindly come to rescue of farmers and the agricultural labourers and provide necessary funds for implementing these contingency plans, which have been formulated by my State, for fodder supply, drinking water supply in rural and urban sectors and create employment opportunities, social security, and for protecting the health of the citizens. I also request that the Central assistance sought by the State should be sanctioned and allocated to Andhra Pradesh, as early as possible for mitigating the drought situation in the State. I appeal to the Government to consider the requests of all States. Mr. Pachouri has already mentioned this. The situation in some other States is also very grave. So, you should come to the rescue of the States. I will go to the extent of saying, if necessary, divert the funds from other sectors to save the millions of people, who are affected by this drought.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Madam, this is the worst drought our country witnessed in the last 30 years. In the last session, we discussed this matter seriously. The drought has its own impact on the economy of our country. Immediately after the Kharif season was over, it was reported that rice production declined by nearly about 15.48 per cent. It was also reported in the newspapers that of the last seven years, foodgrains production of this year was the least. It was also reported that water situation in 70 reservoirs was very critical. We discussed this issue in the last session, and, the Government also made some announcements. The Prime Minister announced some relief packages like waiving of interest, etc. The Government also appointed a High-Level Committee to examine the issue. It was also reported that the Ministry of Agriculture had devised a formula to tackle the situation. But, it is unfortunate to note here that though three months have passed, the Government has not yet been able to tackle the situation. The peninsular areas in our country are Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karanataka, and Kerala. This year, Andhra Pradesh is declared as drought-hit State. In Tamil Nadu also, except Chennai, every part is declared as drought hit. Karnataka is also facing the same situation. Kerala also faced similar draught. Madam, this is the situation and the Government has failed to provide adequate relief to the drought-hit States. Kerala had requested for a relief of Rs.1022 crores to compensate the loss suffered due to drought. Actually, the situation in Kerala is totally different

from other States. The Central Team, when visited our State, had assured that they will provide relief according to the size of crops damaged. But, in Kerala, cash crops like coconut and rubber are sown. So, naturally, in case of cash crops, the loss would be much more. Therefore, I would suggest that, in respect of Kerala, the formula on the basis of which the relief is provided should be changed. The present formula which says that laws for agricultural input subsidy have been liberalised with even 50 per cent of the damage qualifying for assistance, is not fully correct. As per the earlier law, the States were eligible for compensation irrespective of the extent of the damage. As per the revised laws, assistance is provided only when more than 50 per cent of the crop is damaged. So that in a State like Kerala, where 60 per cent of the crops are cash crops, we are not getting the appropriate assistance. I suggest that, in respect of Kerala, this formula should be changed. Secondly, Madam, the Government has announced so many programmes. But, a serious problem is arising after the discussion which we had during the last Session. Now, the Government has announced that the Finance Ministry is going to cut down the Budget allocations for different Ministries. Now, what would be the impact of this cut on the Calamity Relief Programme, on the employment generation programmes, on the agricultural sector, etc.? That has to be explained before the general public because, people are afraid that if such a cut is imposed, what would be its impact in the scenario of an unprecedented drought. So, that aspect needs to be explained in detail in this august House.

Then, Madam, there is the Prime Minister's assurance on waiving the loan amount. For this purpose, the NABARD and Government should give sufficient assistance to the commercial banks as well as to the cooperative banks, otherwise, these benefits will not be passed on to the peasants who are facing the acute problem of drought. The cooperative banks are financially not in a position to extend this facility of waiving the interest. Naturally, the Central Government has to come up with a package with regard to the waiving of interest for the peasants who have taken the loan from the cooperative banks.

Secondly, Madam, there is an assurance with regard to Calamity Relief Fund. But, they are not giving it in single instalment. What happens is that the Government is giving these assistances only in instalments. They are giving it as 'first part of the instalment', 'second part of the instalment', etc. Madam, I think that in this acute situation, you should not give the

bureaucrats an opportunity to exploit the situation. If you handle the situation in the way you are doing, what will happen is that this bureaucratic thing will come in between, and the benefit and the relief will not percolate to the rural villages.

The third thing, Madam, is with regard to giving adequate support for drinking water and for irrigation purposes. The Government is saying, 'We will give you water after 40 years.' Madam, the drought is already there. The drought is there for the last three years, and we are talking about Rs. 5,96,000 crores and all that, but we do not have sufficient funds to provide for the Budget allocation. This kind of myopic attitude is not expected from a respectable and responsive Government. Unfortunately, this Government is coming with such rhetoric which is not going to be fulfilled in the given condition which is prevailing in this country.

Then, Madam, I would like to talk about the agricultural input. In the Ninth Plan, the agricultural sector was given a priority. But as far as the Tenth Plan is concerned, this priority was not visible. The Government has to clearly say before the people as to what its stand is. You should not talk more on temple rather you talk more about the welfare of the people, that would be helpful for the country.

Then Madam, the problem of water sharing is also there. I think in this time of drought, there should be a specific scheme of water distribution. Madam, rather than creating a situation of conflict among the States, some kind of scheme for sharing of water in the time of distress between one State and another should be there. So, my suggestion is that the Government should come out with some proposals with regard to the sharing of water during the drought situation.

Then, Madam, with regard to the poor and backward sections of our society, I would like to say that the 'Food for Work Programme' is very important. For the agricultural workers and landless labourers, the drought situation has created a big problem. They are migrating from rural areas to the urban towns, and they are not getting any work. So, for them, the Food for Work Programme and strengthening of the Public Distribution System is a must. Unfortunately, Madam, we have 16 million tonnes of foodgrains in the FCI. Whatever food subsidy is being given by the Government in the Budget, we are spending it only for preserving the foodstuffs in the FCI godowns, and not for providing foodstuffs for the economically vulnerable sections, the agricultural labourers and the landless

people. In such a situation, I think the Government should change the present policy with regard to its BPL and APL criteria. The purchasing power of the rural poor is very low. They don't have capacity to purchase foodgrains at BPL rate. In villages, the Government is announcing so many programmes, like the Antyodaya, but most of the people are not getting the benefit. In the Antyodaya Programme, you have criteria, which is not providing adequate support to the poor people. In a big village, only four or five people are getting benefits under the Antyodaya Programme. In a big city like Cochin, only one person is eligible under this Programme. This is the situation. This shows very callous attitude on the part of the Government towards the poor people. With regard to the Public Distribution System, when we have so much of foodgrains in the FCI godowns, even then some ugly incidents like starvation deaths are taking place. In order to tackle this problem, a specific programme should be started to ensure equitable distribution of foodgrains. Under the Food-for-Work Programme, in a village having population of 2,500, for instance, only 60 people are getting the benefit. Still, we are thinking about some specific programmes like digging of wells, etc. In most of these cases, *Thekadars*, contractors are coming, and they are using machines. They are not providing work to the poor people. So, there should be some specific programme and a change is needed in the implementation of the Food-for-Work Programme so that more employment could be provided to the rural poor, who have been affected by the drought situation. So, this Government should come up with a specific programme and new food-for-work programme. As far as the PDS is concerned, the Government should come up with a specific programme to provide food for the rural poor. There should not be any BPL or APL criteria for drought-affected areas. The hon. Prime Minister has assured this House that he would call an all-party meeting to discuss about the grave situation prevailing in this country -- regarding the starvation deaths and suicides by farmers. On this occasion, I would like to request the Government that the hon. Prime Minister has to call an all-party meeting to discuss the failure of the Government, to check the drought situation as well as the situation that is prevailing in the rural areas wherein farmers are committing suicides and agricultural workers are dying due to starvation. So, in this situation, the Government has to come up with specific programmes instead of announcements, which are not going to be fulfilled. So, this Government has to come up with specific programme and the Government has to give adequate support to the States, which have been adversely affected due to vagaries of the monsoon. I hope, due to this

discussion in this august House, the Government *(Time-bell)* will come up with a proposal unlike last time when some speeches took place, but nothing happened after that. It should not happen again. The hon. Prime Minister has to call an all-party meeting, and the Agriculture Minister also has to come up with some specific programmes, which should be implemented properly.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): महोदया, सबसे पहले तो मैं इस चर्चा को उठाने वाले अपने मित्र श्री सुरेश पचौरी जी से यह जानना चाहता हूं कि वे किस सूखे पर बहस करना चाहते हैं, जो बीत गया है, उस पर या जो आने वाला है, उस पर ? दो-चार महीनों में वह हालत फिर आने वाली है । असल में हम लोग अपने गांवों में यदि पुराना कैलेंडर भी टंगा रहता है तो उसको पलटते रहते हैं, जब तक कि नया नहीं मिलता । हमें लगता है कि इस सदन में गांव की वही परंपरा चल रही है । लोकतंत्र में जब चर्चा के लिए संसद का कैलेंडर पुराना पड़ जाए, जब मामला गरम हो, उस समय उस पर बहस न हो और उसका निदान न हो तो इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को कोई बचा नहीं सकता है । इतने महीनों बाद सूखा राहत पर हम लोग यहां बहस कर रहे हैं । जितने लोग सूखे और अकाल के कारण मर गए हैं, उतने लोग तो अब की बार जो सरदी पड़ी थी, उसी में मर गए हैं । हम पुरानी बात को लेकर जुगाली कर रहे हैं । एक तो मेरी यह शिकायत है ।

दूसरी बात यह है कि पिछली बार जब यहां सूखे और राहत कार्य पर बहस हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उसमे हस्तक्षेप किया था । मैं कृषि मंत्री जी से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि एक बार मैं उनसे कह चुका हूं और वे यही बोला करते हैं कि राहत कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । तो अब आपसे कहने से क्या फायदा। प्रधान मंत्री जी ने जरूर यह कहा। आजकल यह रोग चला है केन्द्र सरकार की तरफ से। पोटा का इस्तेमाल कोई राज्य सरकार कर दे तो सरकार बोल देती है कि राज्य सरकार के हाथ में है हम क्या करे। तो हर बात पर राज्य सरकार। तो यह राहत कार्य के बारे में भी राज्य सरकार पर फेंक दिया जाता है और लगता है कि मुद्दे से जवाब भागने वाला है। लेकिन हम इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने पिछली बार यह कहा था कि लोग भूख से कैसे मरने चाहिए। हमको लग रहा था कि यह कविता बना रहे हैं। किससे सवाल पूछ रहे हैं। आप देश के मालिक हैं, लोग मर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लोग भूख से कैसे मरने चाहिए। अगला वाक्य था कि जितनी रिपोर्ट आई है भूख से मरने की उतने लोग नहीं मरे। इसके मायने कुछ लोग तो मरे ही हैं न। तो वह कैसे मरने चाहिए, यह हम अजित सिंह जी की मार्फत प्रधान मंत्री जी से जानना चाहेंगे। आप देश के मालिक हैं। अभाव आ गया है और इस समय मौसम का कलेंडर भी बिगड़ रहा है। तब कितना सूखा पड़ेगा, तब कितनी सरदी होगी, तब कितनी बारिश होगी आपका मौसम विभाग इस बारे में फेल कर गया है। पिछली बार सूखा पड़ा था तब भी मौसम विभाग के लोग बोलते थे कि पहली जुलाई तक पानी बरस जाएगा। पहली जुलाई बीत गई तब बोलते थे कि मानसून दूसरी तरफ चला गया, 15 को पानी बरसेगा। मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि गैर जानकारी में हो। लेकिन मौसम का मिजाज बदल रहा है। क्यों बदल रहा है इस पर यहां बहस नहीं करनी है। हम समझते हैं कि हमारे मौसम विभाग के अधिकारी अक्षम हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और अंदाज पर कुछ भी बोल देते हैं। यह बाढ़ वाले मसले पर भी अंदाज पर बोल देते हैं जो पहले से

इशारा करते हैं बाढ़ का। तो मौसम का मिजाज बदला, इस साल भी सूखा पड़ सकता है। हालांकि पिछला सूखा सवा सौ साल के बाद पड़ा था। अब की बार लोगों ने सरदी के बारे में कहा है कि 100 साल तक ऐसी सरदी नहीं पड़ी थी। बूढ़े लोग बोलते थे। प्रधान मंत्री जी ने जब यह कहा कि जितनी रिपोर्ट आई सब मौतें भूख से ही नहीं हैं। मैं बलिया जिले में जा रहा था, वहां किरपाल पुर एक गांव है। लोगों ने बताया कि यहां एक 70 साल की बुढ़िया भूख से मर गई। मैं उसके गांव चला गया। वहां गया तो गांव के लोगों ने बताया कि उसके घर में कोई नहीं था तथा चार महीने पहले इसके मायके से 10 किलो मक्का आई थी और उसी को खाकर वह गुजर कर रही थी तथा अब 6-7 दिनों से उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। इस बारे में बलिया के कलक्टर ने छाप दिया कि भूख से मौत नहीं हुई बीमारी से मौत हुई है। यह जो अफसर बैठे हैं, लगता है कि इनमें ह्रदयहीनता आ गई है। यह सच है कि सूखा पड़ने के बाद गरीब के घर में भूख आएगी, भूख आने के बाद खाना नहीं मिला तो मौत आएगी। वह भूख की मौत नहीं कहेगा, क्योंकि भूख आने के बाद 10 दिन, 15 दिन के बाद उसको कुपोषण की बीमारी हो जाएगी और आदमी मर जाता है। प्रधान मंत्री जी ने भी कह दिया है कि जितनी मौतें हुई हैं वह सब सच नहीं है। मुझे वह 70 साल की बुढ़िया याद आ गई जो चार महीने से 10 किलो मक्का खाकर के गुजर कर रही थी और 7-8 दिनों से उसको खाना नहीं मिला था। मैं कलक्टर का बयान पढ़ रहा था, कितनी मजबूरी में हम लोग हैं। इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं, सूखा पड़ गया, प्रकृति विपरीत चली गई। हम दोष नहीं दे रहे हैं भ्रष्टाचार का क्योंकि कुदरत का खेल है, लेकिन जो हालत चल रही है उस पर तो हमको बहस करनी पड़ेगी, उसका कहीं न कहीं निदान करना पड़ेगा। जहां पर वह बुढ़िया मरी थी, वहां से चार फरलांग की दूरी पर एक मशहूर मिठाई की दुकान थी। लोग वहां से मिठाई खरीदते थे, हमने भी कई बार खरीदी है। उस बुढ़िया की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह जबरदस्ती जाकर मिठाई उठाकर खा ले और अपनी जिंदगी बचा ले। हिन्दुस्तान में जो सरकारी ज़खीरा है, वहां पर गल्ला सड़ रहा है, प्राईवेट ज़खीरेबाज़ इस तरह के अभाव में मुनाफाखोरी का दौर चला देते हैं। हिन्दुस्तान के गरीब और पीड़ित आदमी में यह दम नहीं है कि अपने बल पर अपने बाजू से जाकर के ताला तोड़ दे और अपनी रोटी का इंतजाम कर ले। लोकतंत्र में सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि जब आदमी भूख से मर रहा हो तो उसकी हिफ़ाज़त का इंतजाम किया जाए, उस पर कविता न की जाए। भूख कविता का विषय हो सकती है, गरीबी कविता का विषय हो सकती है, लेकिन हकीकत में उसका निदान करना कविता का विषय नहीं होगा, वह राज़सत्ता का विषय होता है और वहां पर मजबूरी नहीं दिखाई जा सकती है। किससे सवाल पूछें, अनाज पैदा करने वाले से कि भूख से क्यों मरना चाहिए ? किससे सवाल पूछें, ज़खीरे वाले से या जो सरकार के गोदाम हैं उनके मालिकों से ? किससे पूछा जाये प्रधान मंत्री जी से या जो मर गया है उससे ? यह सवाल क्यों पूछा गया ? हमने सुना था और उस समय हमको बहुत झटका लगा था, हमको तो उस विषय पर बोलना नहीं था। लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों ने आपको अपनी तकदीर और अपनी जिंदगी की बागडोर दी है। हम अपने घर में आजादी से जीते हैं जब तक कि हमको फुरसत है, लेकिन यदि कोई बड़ी आफत आ जाये तो उसका मुकाबला करने के लिए सरकार बनाई जाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी आफत के मौके पर यह सरकार फेल हो जाती है, केवल लफ्फाज़ी करती रहती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ब्याज माफ कर दी गई है। हमने अपने खेत में लगाने के लिए बैंक से एक हजार रुपया कर्जा लिया, उसका सूद होगा 100 रुपया, हमारे खेत से कुछ नहीं निकला। आपने

100 रुपया माफ कर दिया, लेकिन एक हजार रुपया तो हमको कभी न कभी देना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी कंजूसी क्यों हमारी हालत पर ? हम यह कहना चाहते हैं कि कारखाना कपड़ा बनाना बंद कर दे तो भी हम जी सकते हैं। अगर कागज बनाना बंद कर दे तो भी हम जी सकते हैं, अगर हम सीमेंट बनाना बंद कर दें तो भी जी सकते हैं, लेकिन किसान अपने ,खेत से गल्ला पैदा करना बंद कर दे तो हम तीन दिन से ज्यादा नहीं जी सकते हैं। शायद पलटन से भी ज्यादा जरूरी इसका काम है और इतने हल्केपन से उसकी मुसीबत को लिया जा रहा है। हमको वही पुराने ज़माने की हालत में छोड़ा गया है, जिन दिनों जरूरत से कम गल्ला होता था तब भी हिन्दुस्तान में भुखमरी होती थी, हमें विदेश से गल्ला मंगाना पड़ता था और आज जब जरूरत से ज्यादा गल्ला हो रहा है तब भी भुखमरी हो रही है, किसान आत्मदाह कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने एक बात और सूखे के सवाल पर कही। मैं जानबूझकर प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर आज टिका हूं कि सूखे के सवाल पर राजनीति मत करो। हम कहां राजनीति कर रहे हैं? *सूखे का सवाल ऐसा है जिस पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए और* जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनका इंतजाम करना चाहिए। कहीं कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन हमने पढ़ा कि राजस्थान के गवर्नर माननीय अंशुमान सिंह सूखा राहत कामों का निरीक्षण करने एक डिढोर गांव में चले गए तो वहां पर किसी को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया। हम विपक्षी दल तो राजनीति करने वाले माने जाते हैं, राज्यपाल तो राजनीति करने वाले नहीं होते हैं। वे बहुत नाराज हुए। अफसरों ने दो दिन बाद फिर उनका प्रोग्राम रखा और एक तालाब के किनारे गरीब लोगों में अनाज बंटवा दिया। यह अफसरशाही भी बड़ी विचित्र होती है और जब कभी आम जनता की जिंदगी में अभाव आ जाता है तो अफसरों की पौ बारह हो जाती हैं और जो मुनाफाखोरी करने वाले लोग होते हैं, उनकी बहार आ जाती है। यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। यह एक भ्रष्ट प्रणाली मानी जाती है। आम जनता इससे नफरत करती है, क्योंकि वहां पर आप जो चार-पांच रुपये की चीज खरीदने के लिए भाव टांग देते हैं, वह हमको आठ-दस रुपये में मिलेगी और मजबूरन जिंदगी बचाने के लिए वह हमको करना पड़ता है। सबकी परचेज़िंग कैपेसिटी नहीं है कि उन दुकानों पर जाकर उतने में भी खरीद सकें । किसी किसी की जेब में सूखे के समय एक भी पैसा नहीं होता है। और तब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह सबकी रोटी का इंतजाम करे । चाहे सरकारी गोदाम हों, वहां भरपूर गल्ला सड़ रहा है, उसे मुफ्त में छोड़ देना चाहिए । जिस किसी को भी जरूरत हो - कलैक्टर, बी.डी.ओ. पटवारी, सबकी रिपोर्ट लेकर कि कौन भूख से मरने की हालत में है - उसके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा और यह त्वरित गति से करना पड़ेगा । प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे । वह बैठक होते होते, बात होते-होते पता नहीं कितने भूख से मर जाएंगे । ये समस्या को टालने के लिए रास्ते होते हैं राजनीति के और मैं नहीं चाहता कि हम राजनीतिकर्मी जो देश को चलाने के जिम्मेवार माने जाते हैं, वे समस्याओं को टाला करें । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां बहुत गंभीर बहस हो चुकी है, बहुत बार सूखे और राहत कार्यों पर बहस हो चुकी है । केवल एक ही जिम्मेवारी शपथपूर्वक सरकार ले ले, यही सरकार नहीं, जो कोई भी सरकार कभी भी आएगी, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह शपथ ले ले कि हिन्दुस्तान में कोई भी आफत आएगी तो किसी भी हिन्दुस्तानी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा चाहे सरकारी गोदाम खोलना पड़े, मरने वाले की जिंदगी बचाई जाएगी । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Prabha Thakur. She is not present.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Madam, it is very unfortunate that our country has to face a severe drought. Drought is a recurring phenomenon. Every year, a few States are affected by drought. Millions of farmers suffer because of that. They not only incur losses but also suffer a lot. Factors like their crop failure, economic losses and their inability to pay debt are forcing them to end their life. The trend shows suicide by farmers is rising. Every day, we read in newspapers about the farmer committing suicide for his inability to pay the loans he had taken for agriculture. In an agriculture predominant country, this should not happen. We have to find out both long-term and short-term solutions to the problem of drought in our country.

Short-term solutions can include a better management of the existing water resources, crop planning rotation, proper guidance to farmers by the State Government and waiver of loans to farmers. The small and marginal farmers should be given due importance. They should be given financial assistance to withstand the drought conditions. They can be engaged in alternative jobs to help them economically.

So far as long-term measures are concerned, linking of rivers, proper crop planning etc. are the solutions. The Government has initiated action on linking of rivers. This is a welcome step. Now, it is to be seen how the Government moves on this project. Let it not remain only on paper.

The Government has also provided financial relief to the farmers in order to compensate them for the losses suffered in unirrigated areas in the form of a special Drought Relief Price ranging from Rs.5/- to Rs.20/- per quintal. This is inadequate. It should be raised to appropriately compensate the farmers. The States should also ensure a timely flow of institutional credit to the farmers.

I am sorry to point out that the Central Government has not provided enough financial aid to the States. Against the demand for Rs.1,562 crores made by the Karnataka Government, the Central Government has provided only Rs.221 crores. For Madhya Pradesh, against its demand for Rs.790 crores, only Rs.126 crores have been provided, and for Rajasthan, against its demand for Rs.7,519 crores, only Rs.207 crores have been provided. In total, as against the demand for Rs.31,102 cores, only Rs.1,999 crores have been provided.

As per a study, the spectre of drought over a vast area of India could cost the Exchequer over Rs.1,000 crores. This means, allocation for development will be either reduced or diverted to the relief and rehabilitation schemes.

There is a need to solve the inter-State water disputes amicably and in a harmonious manner so as to ensure an equitable availability of water during dry spells. In Karnataka, 186 taluks have been declared as drought-hit areas. The amount released to Karnataka is very meagre. Our hon. Chief Minister made repeated requests for extra foodgrains for "food for work" programme. But nothing has been done so far. I request the hon. Minister to release extra foodgrains to Karnataka as early as possible. It is also important to work out a viable water management system, in view of the unprecedented drought faced by the 14 States during the last year. Indian farmers are very hard working, but weather is not helping them. Drought and untimely rains frustrate their efforts. That makes them commit suicide. The worst sufferers are the small and marginal farmers and landless labourers. Government should ensure that these categories of farmers are not affected and they are properly compensated. Our hon. President, Madam Sonia Gandhi, has requested our hon. Prime Minister to make known in advance the entire allocation that could be given to each State, at least as a projection. So, our hon. Prime Minister should have taken that suggestion and made a note in advance to the States on the allocation they are giving to each State, and also released at least 50 per cent of the capital initially so that the State can ensure an uninterrupted flow of foodgrains in the affected areas. Madam Sonia Gandhi also requested for delegation of powers to the Central Relief Commissioner to respond immediately to the distress signals from the State. Madam, unless you delegate the powers to Central Relief Commissioner, he cannot immediately respond, and he has to take long time because of the long process and the paper work, which takes long time.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY) in the Chair]

So, it will affect the persons more and more. I hope the hon. Minister will take these suggestions and help the people of our country.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, we are discussing about the severe drought situation prevailing in more than 14 States throughout the sub-continent. Sir, even though the Members are expressing their concern about their States, the cumulative effect is

4.00 p.m.

actually a national loss. Therefore, the Government of India, I hope, would take this issue as an urgent national issue and in that perspective, they will consider the issue on a war-footing. Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, last three harvests completely failed. Last year, there were no agricultural activities. Particularly, in 5 districts, nearly 18 lakh agriculture labourers were severely affected even in respect of their basic needs. Previously, there used to be a system. The produce was procured by the former Government. But, during the last two years, this has been almost stopped. Since, the procurement by the present Government is also stopped already, the agricultural production is also affected. In this situation, whatever small quantities they had, they sold in the market at very low prices. Expecting the scarcity of essential commodities, the price has been raised in the market. There was another problem. The Labour Welfare Board for agriculture labourers was constituted by the previous Government in the State. But that is also not functioning now. Therefore, it is difficult to alleviate the sufferings of the agriculturists. The problem is that proper information is not made available to the agriculturists. Due to lack of proper information, they lost even the seeds that they had. Whatever seeds they had, they sowed expecting that they would get the water. Sir, you know how we are affected. After sowing the seeds, they were not able to get the water. Therefore, they lost the seeds also. The agriculturists lost crores of rupees. As you are aware, our economy is based on agriculture. Ours is an agricultural economy. Therefore, the other sectors are also affected. The weavers of Tamil Nadu have been affected in the last two years.

Sir, it is unprecedented in the history of Tamil Nadu that starvation deaths took place there. It took place in the granary of Tamil Nadu, that is, Thanjavur. Starvation deaths took place in the districts of Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, and other areas. Another unprecedented incident is that some agriculturists committed suicide. It is a shame to the whole nation. This is the situation.

Sir, as you are aware, we are unable to come to an amicable settlement regarding the Cauvery water issue. At least, during the time of distress, they should have divided it on *pro rata* basis. That was also not done. A programme was announced that the agriculturists could go to the schools and take mid-day meals. They were reluctant because they were born agriculturists and they used to give food to other people. When they

were asked to take the plates, go to the school and take the food, most of them did not go. Then, another scheme was announced that the agriculturists, who are not actually having fields, might be provided with some rice. But it was to be given only to those people who had already registered with the schools for mid-day meals. Therefore, most of the agriculturists, who do not have any work, are not able to survive. This is the situation in five districts of Tamil Nadu. The entire economy is completely shattered.

Another thing is that nearly 2,10,000 acres of land, which depends on the Periyar Dam, is also affected. If the water is preserved at 152 feet in the Periyar Dam, this 2,10,000 acres of land in the south of Madurai and other areas could be saved. Those areas are also affected. The agriculturists living in Madurai and around, in Ramanathapuram district and other areas are also affected.

Sir, I come from Coimbatore. The population of Coimbatore and Erode districts taken together, is 85 lakhs. More than 50 lakhs of people depend on the Bhavani river for drinking water. There is a problem. Nearly 1.2 lakh hectares of land is irrigated by the Bhavani river. Now, our neighbour, the Kerala Government, has decided to construct a weir in the river. If the weir is constructed, the entire river will be diverted. They have already dug a canal. Within 500 feet of distance, there is another small stream. If these are connected, both the sides are going to be affected. Nearly three-and-a-half lakh acres of land, that is, 1.2 lakh hectares of land, in Tamil Nadu is going to be completely affected. Nearly 50 lakh people are going to suffer due to shortage of drinking water. In Kerala, from a place called Mukkali to Tamil Nadu border, the farmers are utilising 2,000 motor pumps. They are also going to be affected. Why do they want to construct this weir? The local people say that in-between Mukkali and Mannarkkad, an international company has decided to establish a mineral water project. They are not getting the water. That is the reason. This is the pathetic situation. In Mannarkkad taluka, about 20 kilometres away from Mukkali, more than five rivers are running. If the Bhawani is also going to join with that water, then it will be flooded like anything. Mannarkkad itself will be completely submerged in water. Inspite of it, that Government is also doing this. This has created another problem. The problem is that the communal harmony has been little bit affected. A former Minister, Mr. Pongalur Palanisami, with the help of all the sections of the society, has conducted a fast in which he invited the Keralites also

because we wanted to keep the harmony between Tamil Nadu and Kerala. We asked the people to participate in the fast and the Kerala people also addressed the issues, thereby we were able to maintain harmony between Tamil Nadu farmers and Kerala.

Nearly 1.5 lakh Kerala people are living in Coimbatore city itself. A little bit of friction is there. They wanted to avoid it and they want to live as Indians. The Bhawani springs from Tamil Nadu, goes to Kerala and again comes back to Tamil Nadu. There is another problem, which is being created artificially. That is why, we wanted they must give up this plan. When some people alongwith the Press people wanted to have a visit there, an unfortunate incident took place and they were attacked by some people with vested interests.

Therefore, I say that the agriculture is totally affected in Tamil Nadu. Crores and crores of rupees have been already lost and the people are suffering even from lack of basic needs. They are not able to buy the essential commodities. Unless the Central Government comes forward to help in an abundant manner, not in the usual manner, it is very difficult for the agriculturists to live there. Therefore, I request the Central Government, through you, Sir, that they must be considerate and liberal to extend the helping hand not only to the agriculturists in Tamil Nadu but in other States throughout India and see this as a national calamity, national issue and national loss. Therefore, I hope the Central Government will take appropriate action and see that the suffering of the agriculturists is alleviated.

श्री लालू प्रसाद (बिहार): महोदय, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है । हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी कहा करते थे कि भारत, दिल्ली नहीं, खेत और खलिहानों की मेढ़ों पर बसता है । इस देश की एक अरब, लगभग पांच करोड़ जनसंख्या पर हम लोग पहुंचे हैं । कृषि ही एकमात्र निदान है । कृषि और पशुधन ही हमारी अर्थव्यवस्था है । महोदय, जिस तरह से इंसान धोखेबाज़ होता चला जा रहा है उसी तरह से प्रकृति का मन और मिजाज भी बदल रहा है । इंसान बदल रहा है तो प्रकृति भी बदलेगी । महोदय कुछ राज्यों को छोड़ दे तो देश भर में बड़ा भारी सूखा पड़ा हुआ है । राजस्थान से लेकर तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में पड़ा हुआ है । जिस गुजरात में राम के भक्त हो, जहां राम का नाम ज्यादा लिया जाता है, वहां भी चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं । दिल्ली में जो सरकार बनी है उसे इससे कोई मतलब नहीं है । यह इस देश की मूल समस्या है । इस देश में जी.डी.पी. चार परसेंट तक पहुंचा है । यह प्रमाणित हो गया है कि ये इस देश को अमरीका बनाना चाहते हैं, सिंगापुर बनाना चाहते हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं । डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा करते हैं । देश की चिंता भारत सरकार को, भाजपा की सरकार को नहीं है क्योंकि ये किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करते । यह तो शहर से

निकल कर, मुश्किल से, भगवान जी का नाम ले कर, चुनाव हुआ था और किसी तरह से यहां पर बैठे हुए हैं । महोदय, अब पता नहीं हमारे भाई अजित सिंह जी क्या करेंगे, यह तो अमरीका से पढ़ कर आए हैं । चौधरी साहब की अवधारणा इनके विषय में हम लोगों की थी, देखें कहां तक यह सफल होते हैं । उन बातों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि यह तुरंत तुनक मिजाज हैं, बिगड़ जाते हैं । इसलिए हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते । इनके हाथ में भारत की कृषि है । महोदय, यह जो सूखा है, आगे कोई गारंटी नहीं है कि फिर बारिश होगी, अब पता नहीं इसके लिए क्या सोच है, क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है ? गेहूं दे दिया तो फलां दे दिया । राजस्थान में एक्सप्लोयट करके ये तीन-चार सीट जीत गए तो पता नहीं क्या समझ गए । यहां पर चर्चा हुई, आप गेहूं की बात तो छोड़िए, यहां पर तो पानी के सवाल पर लड़ाई होने वाली है । उसके लिए क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं, इस पर हम सब को सोचना है । अकेले इनकी ही जिम्मेदारी नहीं है । कल इस देश के अंदर जो मार-काट होने वाली है, भाई-भाई और राज-राज में जो मार-काट होगी, आप खेती की बात तो छोड़ दीजिए, यह पीने के पानी के लिए लड़ाई होगी और बिहार को छोड़ करके बाकी जगह बड़ा भारी विद्रोह होना है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे बिहार को इतना अंडरग्राउंड वॉटर दिया है कि उसकी हमारे यहां कमी नहीं है । अब यह बचेगा तो वहां से पीने का पानी भिजवायेंगे । महोदय, बड़े पैमाने पर जो राहत का, बचाव का काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । बिहार में जितना धान का रोपण समय पर होना चाहिए था वह नहीं हुआ । बारिश नहीं होने की वजह से राज्य का धान पैदा करने का जो लक्ष्य था उसमें भी कमी आई है । हम सूखा प्रभावित राज्यों के लोग सरकार से जानना चाहते हैं और मांग रखना चाहते हैं कि सीआरएफ का फंड तो फिक्स है, यह तो निर्धारित है कि किस राज्य को कितना मिलेगा । आज से नहीं, हम लोग कई बार आए, कई बार मुख्य मंत्रियों की कमेटी बनती थी और कहा जाता था कि पैसा ले जाओ, लेकिन वह रिलीज़ नहीं करते थे । यह सड़ा हुआ गेहूं, जो आप गोदाम में रखे हुए हैं, उसमें जो इस देश में घपला हुआ है, वह आप जानते हैं । यह आपका गेहूं क्या कोई लेना चाहता है ? बड़ी आसानी से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कह दिया जाता है । अब तो अनाज के पैदा होने में काफी लंबा ड्यूरेशन होता है, लेकिन यह जो हमारा ग्रेन है, उसके बारे में पता नहीं क्या हो रहा है, वह तो एक तरह से समाप्त हो रहा है । तमिलनाडु के लोग और कर्नाटक के लोग और दक्षिण भारत के लोग, जो हमारे भाई-बन्धु और प्रतिनिधि हैं, यह बताइये अनाज में जो दलित अनाज था, बैकवर्ड अनाज था जो इस देश का सीड था, वह तो समाप्त कर रहे हैं । जैसे मरुआ था, जिसको ये लोग रागी बोलते हैं, मक्का था, ज्वार था, टोनी था, कोनी था, जो कि शॉर्ट पीरियड मे हो जाता था, जिसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं थी और साठी धान था । साठी हो कर साठ दिन, अब वर्षा हो कर रात-दिन । यह भारत का सीड था । पूरे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों का सीड था । लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि गैट में समझौता ला करके ये निरवंश बीज ला रहे हैं । अनाज में जो ऊंची जाति का अनाज है, राइस और व्हीट, इन दो पर ही इनका ध्यान है और इसी का बीज ला कर क्या कर रहे हैं? इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । चौधरी चरण सिंह जी, स्व0 राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खेतों में जा कर देखो और ध्यान दो कि जो मरुआ है, जो मकई है, बाजरा है, जनेरा है, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । केवल बाहर के व्हीट पर ही ध्यान दिया जा रहा है । धान के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता है लेकिन इसके लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं है । असल में बात यह है कि हम लोग सुनते हैं और यह बात सही भी है कि जब शासक और राजा अत्याचारी व पापाचारी हो जाता है

तो प्रकृति भी धोखा देती है । महोदय, आपको याद होगा, आपको तो इतिहास की जानकारी है और धर्म की आपको हम से ज्यादा जानकारी होगी कि राजा जनक के समय मे इसी तरह से भयानक सूखा पड़ा था । याद करो, राजा जनक थे, आपको जानना चाहिए ...**(व्यवधान)**...अजित जी, आपको खुद जानना चाहिए, आप उस पार्टी में है, वे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं । उस मे हमारे उस समय के जितने ऋषि-महर्षि थे, उन का खून वे राक्षस घड़े मे डालकर रखते थे । उन दिनों राजा जनक का शासन था । उन दिनों में वहां पर हर तरह का अत्याचार ये लोग करते थे । ऊपर से प्रकृति का प्रकोप था । इंसान सूखे से मर रहे थे । तब यह बात आई कि जब राजा जनक हल चलाएंगे तो बारिश होगी । राजा जनक हल लेकर गए तो वहां खेतों में ऋषि-महर्षियों का खून गड़ा हुआ था, हल लगने से उस से सीता जी निकलीं । वहां सीता का जन्म हुआ । ...**(व्यवधान)**...आप पता कर लीजिए । आप जिस अयोध्या की बात करते हैं, आप पता कर लीजिए, अयोध्या से राम और सीता को वहां से भगाया । आप देखें कि रोज यह शासन लोगों का खून खींच रहा है । ये इतने अत्याचारी हो गए हैं कि मानवता कराह रही है। ये राम, रहीम के बंदों में नफरत पैदा कर रहे हैं । चारों तरफ दंगा-फसाद और मारकाट मची हुई हैं । यह सब प्रकृति देख रही है कि ये शासक अत्याचारी हैं । अब ये लोग तो हल चलाने लायक भी नहीं हैं । हम सूखे की यहां चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हल चलाने के लायक नहीं हैं । इसलिए मैं सिर्फ आलोचना नही करता, मेरा सुझाव है कि हमारे यहां शार्ट रेंज में जो अनाज होता है, उस का संग्रह कर किसानों को दिया जाए । उन का कर्ज माफ किया जाए । जब तक बारिश नहीं होती है तब तक लोगों के लिए रोजी-रोटी का प्रबंध सरकार को करना चाहिए । आप जब सारा कूड़ा-करकट माटी के भाव बेच रहे हैं तो वह पैसा किसानों के लिए लगाइए । आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत के पशु को फाडर भी नहीं मिल रहा है । आप गाय माता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज गाय भूख से मर रही हैं । ये लोग दिल्ली में बैठकर आराम कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन राम से इन को कोई मतलब नहीं है । आज देश का किसान आत्म-हत्या कर रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि बी0जे0पी0 के साथ जो एन0डी0ए0 के दूसरे दल हैं, वे भी आखिर क्या कर रहे हैं । ये भी नाइंसाफी कर रहे हैं । आप काहे इन के साथ बैठे हुए हैं ? तमिलनाडु से लेकर जो भी दल यहां बैठे हुए हैं, ये कोई विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं ? इन को किसानो की चिंता नहीं है । यह "भा0ज0पा0" सरकार ...**(व्यवधान)**... माता जी, आप बैठिए । यह "भा0ज0पा0" सरकार किसान विरोधी सरकार है, गांव विरोधी सरकार है । किसानो से इन को कोई मतलब नहीं है । ...**(व्यवधान)**... आप हमारे यहां जाकर देखिए । महोदय, इतनी शीत-लहर नही थी, फिर भी हम एक-एक तुलसी का पत्ता खोज रहे हैं, पूरे बिहार के लोग एक-एक तुलसी का पत्ता खोज रहे हैं । इन के पाप से, इन के कहर से सारे तुलसी के पत्ते सूख गए हैं । उत्तर प्रदेश मे भी सूखा है । उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ...**(व्यवधान)**...आप बात सुनिए ।

श्रीमती गुरचरण कौर (पंजाब): आप अपने अंदर झांककर देखिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : हमारे यहां बिहार में सूफियों, संतों का राज है । वहां जाकर दर्शन कीजिए, वहां जाकर देखिए । महोदय, हम बिहार के लोग एक ही फ्रूट मेंगो खाते हैं, आम खाते हैं । उस आम में कहर से मंजर नहीं आया । इसीलिए मैं महिला बिल का विरोध करता हूँ । आपको अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो न जाने यहां पर क्या होगा ? इसलिए मैं विरोध करता हूँ । ...**(व्यवधान)**...माफ करिए, अब आपको हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या ?

उपसभाध्यक्ष (श्री पी0 प्रभाकर रेड्डी) : लालू जी, आप अपनी बात बोलिए ।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, बूढे, बूढी, गरीब लोग ठंड के कहर से परेशान हैं । चारों तरफ पेड, पौधे, गाय, जानवर प्रभावित हुए हैं । आम की फसल का नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल पर ठंड ने कहर ढहाया है । हमारा जो चना था, मसूर थी, उस पर भी ठंड का कहर पड़ा है । जो सीआरएफ फंड हमारा था उसमें 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया कि जो गरीब लोग हैं, जिनको ओल्ड ऐज पेंशन देते हैं, जिनको मुफ्त में हम राशन देते हैं, उनको क्या हम कंबल नहीं दे सकते । भारत सरकार को, इनके विभाग को राबड़ी देवी सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है कि जो विकलांग है, गूंगा है, जो गरीब है, उसको कंबल दिया जाए । महोदय, अभी भी ठंड का कहर चल रहा है और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रकृति का मिजाज होता है वह अपने अनुसार चलता है । चैत्र के महीने में पंडित जी गाय बेचकर कंबल खरीदे थे । तो 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इनके पास भेजा गया, लेकिन यह बैठे हुए लोग, हीटर में रहने वाले लोग हैं । हम चाहते हैं कि इन गरीबों को एक एक कंबल दे दिया जाए, जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया । हम आशा करते हैं और कृषि मंत्री जी से यह डिमांड करते हैं कि 30 करोड़ का जो प्रस्ताव आपके विभाग में आया है, जहां गूंगा, विकलांग, गरीब आदमी है, जिनको मुफ्त राशन देते हैं, उनको एक एक कंबल दे दिया जाए । हमारा फंड का पैसा है । हमने यही मांग की कि इसमें 30 करोड़ का कंबल आप दे दिया जाए, नहीं तो आप कंबल खरीद कर हमारे यहां भेजिए । तो हाहाकार है ।

महोदय, एक तरफ सुखाड़ है, दूसरी तरफ बाढ़ है, तीसरी तरफ प्रकृति का कहर है, शीत लहर चल रही है । हमको तो लगता है मालथस थ्योरी, जो कहा गया है, यह कैसे कंट्रोल किया जाएगा ? यह तो प्रकृति है, जब गरमी चलेगी तो गरमी चलेगी, जब पानी पड़ेगा तो पानी पड़ेगा, जब सूखा पड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, इसलिए सावधान । सावधान हो जाना पड़ेगा । यह जिम्मेदारी आपकी है । अजित सिंह जी, आप योजना बनाइए, जिसमें सारी पोलिटिकल पार्टी के लोगों को, राज्यों के लोगों को, जो राजनेता प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको बुलाइए और कैसे हम सूखे से निजात पा सकते हैं, इसके लिए एक कार्य-योजना बनाने की जरूरत है और उस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, सिर्फ खानापूर्ति की जरूरत नहीं है । आप यह जो डाटा देते हैं कि इस राज्य को इतना दिया, उस राज्य को उतना दिया , इससे काम चलने वाला नहीं । आप जाकर पूछिए किसानों के बीच में, किसानों को क्या मिलता है ? सब पैसा कहां चला जाता है, क्या हो जाता है ? आपका भेजा हुआ गेहूं सड़ा होता है, उससे तो अच्छा बाजार में मिलता है । यह सड़ा हुआ गेहूं, गोदाम में मूषा का काटा हुआ, घुन लगा हुआ, दीमक का खाया हुआ गेहूं आप जो भिजवा रहे हैं, क्या वह कोई आदमी खाएगा ? इससे तो फूड पॉयजन हो जाता है। इसलिए आपको इसको देखना होगा ।

महोदय, हमारा मानना है कि यह सरकार गांव और किसान विरोधी सरकार है और इसलिए देश के किसानों, सभी नौजवान, गरीब, मजदूर, खेतिहर लोग एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंको । जब तक यह सरकार रहेगी, बारिश होने वाली नहीं है क्योंकि ये लोग जो सरकार में हैं, इनके अत्याचार से प्रकृति भी कांप रही है ।

महोदय, अंत में हम यही मांग करते हैं कि हमारे यहां शीत कहर से प्रभावित लोगों का आप इंतजाम करिए । धन्यवाद ।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to Shri Suresh Pachouri for raising the discussion on this very, very important situation that the country is confronted with. There is an unprecedented drought. Sir, I would like to express my severe anguish that even after this sort of very serious discussion, the hon'ble Agriculture Minister could break into laughter. When the entire nation is in agony, when people of more than 14 States are dying, particularly the poor people, the marginalised people, the peasants, the poorest of the poor, the faces of the administrators of this country, who are ruling this country, are not replete with the anxiety that is required. Sir, I am ashamed to say that even after 55 or 56 years of our Independence, the people are dying in thousands either because of severe drought or floods; and all those who survive, they die because of sun-stroke or some other natural calamities. I am more agonised because the Government figures say that there are 63 million tonnes of foodgrains which are stocked in the FCI godowns and a number of hon. Members have referred to it but even that huge stock of foodgrains, the peasants, a large number of peasants who are responsible for this stockpiling, at the time of their need, those are not being sent to them and they do not have the purchasing capacity because of the wrong economic policies pursued by the present Government. The people have been stripped off their purchasing capacity and so even the people who are in so-called Above the Poverty Line level, they are also not able to purchase. The Government accepts, according to the Government figures, 26 per cent of the population is living below the poverty line. How are they living? By what means they are living? The present Government is not at all serious to know about it. In some of the cities and some of the villages, even the domestic animals, perhaps, live in a better condition. It is to the pleasure of the rich of this country -- whether they are the urban rich or the rural rich -- that this Government's policies are directed. Sir, in so far as the dimension of drought is concerned, I am referring to the answer given by the hon. Agriculture Minister on 9th August, 2002, where he had admitted that 160 districts had experienced scanty rainfall between the period 1.6.2002 to 31.7.2002 and 158 districts had experienced deficient rainfall. May I ask the hon. Agricultural Minister, through you, Sir, that whether he or his department at all thought of any climate policy? I raised the demand through special mention in the last session that a climate policy should be in place in this country, so that we can go for some long-term measures.

No long-term measures are there. I fully agree with Shri Ramachandraiah, the Leader of the Telugu Desam Party, in this House, that it is not the drought ordained by the nature, which is responsible for the sad plight of the people, but it is actually the drought of action on the part of the Central Government that is responsible for the agonising situation of the people. What is required is action on the part of the Government. But the Government is inactive. The Government is sitting careless, absolutely careless.

There is no climate policy in place, there is no natural disaster management policy in place. For the last three years the country has been experiencing cyclone in Orissa and Gujarat. There was an unprecedented earthquake in Gujarat. Almost 85 per cent of our country's land is vulnerable to natural calamities, but there is no disaster management policy as envisaged by the Government of India. So, may I request, through you, Sir, that the Government should wake up from its slumber and immediately come forward with a permanent disaster management policy. Before I get into the main text of my deliberation, I would ask the hon. Minister whether the Tenth Finance Commission had recommended that there should be a National Calamity Relief Fund. The Eleventh Finance Commission is in existence now and we are also in the midst of the Tenth Five Year Plan. I would like to know whether this Fund was created. If it had been created, what were the modalities of the operation of this Fund?

Sir, I was a little perplexed to know that, in reply to the Unstarred Question No.2505 on 9.8.2002, the Minister of State for Agriculture, Shri Hukumdeo Narayan Yadav -- I do not know whether he is still continuing to be the Minister, because there have been so frequent changes that I fail to keep a track of them -- had said that Andhra Pradesh got a good share from the National Calamity Relief Fund. While replying to the same question, he had also informed the House that Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and, to some extent, Haryana were the four most drought-affected States. I find here that Madhya Pradesh has got Rs.25.89 crores, Andhra Pradesh has got Rs. 81.89 crores, Haryana has got Rs.33.615 crores; and then you also have the States of Himachal Pradesh, Karnanata and so on. But, today, I got a little perplexed. The leader of the Telegu Desam Party, perhaps, rightly mentioned that Andhra Pradesh did not get its due share or the amount that was due to it. So, what are the facts? I would like to know whether the reply of the hon. Minister of State for Agriculture was correct or what the leader of the TDP had mentioned. I

fail to understand it. Sometimes I feel it has become a fashion for many of the Ministers to mislead the House. Today, in the morning also, we observed that none other than the Deputy Prime Minister himself was misleading the House; or, he was resorting to deceptive answers. So, this has become a practice .in this House. I also agree with Shri Lalu Prasad Yadav when he says that till the time this Government exists in this country, perhaps, these problems cannot be taken care of; perhaps, these problems have become perennial. Even in a situation where people are dying of starvation, the Government is so involved in suppressing the facts, it is trying to divert the attention of the people. The party which is running the Government, the BJP, and its cohorts, the different outfits of the *Sangh Parivar*, are still resorting to communal disturbances; they are still inciting the people to go in for the construction of the temple. Is it the time that the temple and the mosque issue should be raised and raked up? I fully agree with Shri Yerran Naidu, who rightly said on television that 14 States were suffering from severe drought conditions and people were dying of starvation. The poorest of the poor are dying. The peasants are dying of starvation. Is it the time to rake up the issue of the temple and the mosque? Is it the time to rake up the issue of the worship of a very old idol in Bhojshala of Dhar District in Madhya Pradesh? Yesterday only, it was demanded by the Hindu Jagran Manch. Who is responsible for this? Are they caring for the people of this country? Are they caring about the nation? I firmly believe that this Government is not at all careful about the...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Please conclude now.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I am concluding, Sir. So, this Government is not at all careful about protecting the interests of the people of this country, particularly the interests of the poorest of the poor. Sir, this year, India has faced the worst possible drought situation in recent times. There is rampant hunger, a serious drinking water scarcity and acute shortage of water for irrigation in a large number of areas. What is happening? The youth in the drought-affected areas are migrating from the villages to the other areas, leaving the old people alone. Now, these old people cannot go and ask for relief measures. The relief does not reach the old people. They are dying of starvation. Sir, this Government do not have any connection with the grassroots. It has been widely reported that in several drought-affected villages, the poorest of the poor; the most needy families fail to get the necessary assistance for their survival. The younger

members of those families mostly migrate at an early stage, while the elderly people are left behind, and they are not able to access the available relief. Therefore, it is important that such a mechanism is evolved by the Central Government, by the Government of India, that relief measures can also reach the affected people, and they are not left to the mercy of the officials. Even after two years of Gujarat Earthquake, a large number of poor people are still affected in Bhuj and Kutch districts, and the bureaucracy has taken advantage of this. And to guard this and to suppress the facts, to divert the attention of the people, these people are resorting to things like inciting communal passions. So, I would urge upon the Government, through you, Sir, that there should be a proper direction to the Government, that this Government must take care of this situation, this perennial problem. A permanent solution has to be found out; some permanent measures have to be taken; some permanent measures have to be made so that this sort of things are not repeated in the days to come, and we are not forced to discuss all these things in future, and we are not further ashamed because of this serious problem of natural calamity. With these words, I conclude.

श्री गया सिंह (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। बाढ़ के बारे में आज दूसरी बार हम लोग बहस कर रहे हैं इस हाऊस में और अभी काफी माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा। मैं दो-तीन बातें रखना चाहता हूं। हमारी जो सरकार है वह बड़े जोर-जोर से चिल्लाती है कि पूरे देश में सम्पूर्ण ग्राम विकास चला रहे हैं, भूख से नहीं मरने देंगे। महोदय, हाल ही में मैं आन्ध्रा, छत्तीस गढ़, बस्तर जिला, उड़ीसा व राजस्थान के क्षेत्रों में गया था। जितने जोर से हमारे अजित जी यहां बोलते हैं, नीचे में वहां कुछ पता नहीं चलता है। मैंने कई जगह राज्य सरकारों से बातें की। उन्होंने कहा कि जितनी हमको मदद चाहिए वह हमको केन्द्र से नहीं मिल रही है। मैं बस्तर संभाग के नीचे गंतीवाड़ा में गया था जो आदिवासियों का इलाका है। वहां पी0डब्लू0जी0 आर्गनाइजेशन है जिसके खिलाफ बैन है। अगर वहां आदिवासी इलाके में पी0डब्लू0जी0 आर्गनाइजेशन न हो तो सैकड़ों आदिवासी इस अकाल में मर गए होते। अखबार वालों ने हमसे पूछा कि आप उनका समर्थन करते हैं? हमने कहा कि वह हमारा सौतेला भाई है लेकिन उनकी हिंसा की राजनीति से हम सहमत नही हैं। लेकिन आज जिस ढंग से बस्तर जिले में और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों मे जो नक्सलवादी लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं उस तरह से न तो आपकी केन्द्र की सरकार बचा रही है और न वहां की राज्य सरकार ही बचा रही है। हर साल हम इस पर बहस करते हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं। लेकिन सचमुच में काफी लोग मर रहे हैं। लेकिन न तो मीडिया वाले उसकी पूरी रिपोर्ट कर पाते हैं न यहां पूरी सूचना आती है। अभी लालू जी बोल रहे थे। इन्होंने बिहार को बांट दिया। हम भी उससे सहमत थे कि झारखंड अलग बना दिया। लेकिन आज बिहार की क्या हालत हो गई, वह दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। बड़े जोर से यह लोग चिल्ला रहे थे और उसको 50 हजार करोड़ का पैकेज देने वाले थे। लेकिन अब यह उसको बाढ़ से भी नहीं बचा पाते हैं जबकि यहां उनकी टीम भी जाती है। मैं इसी हाऊस में 11 साल से हूं। मैंने पहले की सरकारों से भी इस बारे में पूछा था। तो कहा गया कि अभी वहां सर्वे हो रहा है। अभी तेलगू देशम के लोग बोल

रहे थे। इस सरकार मे जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके बारे में इनका विशेष पैकेज होता है लेकिन जो उनकी सरकार में सहयोगी नहीं है वहां के बारे में इनकी दूसरी नीति होती है। देश एक है, सब जगह के लोगों ने आपको वोट दिया है इसलिए पूरे देश में जहां भी अकाल है, ड्रोट है लोग मर रहे हैं, सब को बराबर दृष्टि से देखिए। अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी सभी एम0पीज0 को मिली है। मैं पढ़ रहा था कि जितनी मांग उन्होंने राजस्थान के लिए की है, उसकी आधी मांग भी आपने पूरी नहीं की है। अभी लालू जी चौधरी साहब के बारे मे बोल रहे थे। उनके भाषण मैंने भी बहुत सुने हैं।

महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संथाल में गया था। मुझे यहां पर कहने में हिचक हो रही है। आप गौ हत्या की बात करते हो। आप उस इलाके मे जाकर देखिए। वहां पर लोग गाय को खा रहे हैं। उन इलाकों के लोग भूख से मरने से पहले गाय को खा रहे हैं। आप गौ हत्या पर कानून बनाने वाले हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो कोई गाय अकाल पीड़ित क्षेत्रो में नहीं बचेगी। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में लोग भूख से मरने के बजाय गाय खा रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में मालूम है? आप इसकी जांच करवाइये। एक कमेटी इस हाउस की बनवाइये और उस ज्वाइंट कमेटी को उन क्षेत्रों में भेजकर के जांच करवाइये। उस कमेटी से सर्वे करवाइये कि क्या स्थिति उन इलाकों की है, जहां पर अकाल पड़ा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। अभी मिश्र जी ने ठीक ही कहा है कि यह पीरिएड तो गुजर रहा है, आगे आने वाले पीरिएड के बारे में सोचिए। हमारे बिहार में कहावत है, " बारात आवे तो कोहरा..।" वाजपेयी जी ने कहा कि हम सभी नदियों को जोड़ देंगे। आप एक साल के लिए तो हैं और कल का पता नहीं। अब अकाल आ गया तो कहते हैं कि हम सब नदियों को जोड़ देंगे । मोरारजीभाई जब प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि दस साल में हम पूरे देश की बेरोजगारी दूर कर देंगे। अब वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम सब नदियों को जोड़ देंगे। एक नदी को तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। आप तमिलनाडु और कर्णाटक की जो नदी है उसको तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए एक साल से लगे हुए हैं और आप पूरे हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। आप इस बात को छोड़िये । आप तत्काल कोई राहत का ऐसा रास्ता निकालिए कि जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनका बचाव हो सके। आप सभी राज्यों को बराबर की दृष्टि से देखिए। जहां पर आपकी हुकूमत है वहां भी और जहां पर नहीं है वहां भी। तीन साल पहले बंगाल में भयंकर बारिश हुई और आप एक साल तक उसका सर्वे कराते रहे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक रात आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कसके बारिश हुई तो रातों रात 400 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। हम लोग आपको ऐसा करते हुए देख रहे हैं। आप इन नीतियों को चेंज करिए। देश के अंदर जहां-जहां भी भयंकर अकाल और सूखा है, वहां पर चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत है आप सबको बराबर की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। हमें आशा है कि आप ऐसा करेंगे। अभी लालू जी ने कहा कि शीतलहर से लोग मर रहे हैं और इन्होंने तीस करोड़ रुपया मांगा। इसके बारे में कहते हैं कि कोई पैसा नहीं देंगे क्योंकि वहां तो लालू जी की सरकार है। वहां लालू जी की सरकार है तो क्या करिएगा। इनकी सरकार तो आगे भी आने वाली है। आप लोग जितनी भी कोशिश करिए, हालांकि हमारी पार्टी इनके खिलाफ है, लेकिन सब लोग कोशिश कर लें, लेकिन लालू जी को हराने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I associate myself with Shri Suresh Pachouri who raised this discussion and I also support the points raised by him with regard to drought situation that we are discussing in this House. Everybody has already expressed the extent of devastation of drought in the whole of country. As we all know, 14 States have been affected. In Andhra Pradesh, out of 1126 Mandals, 925, in Orissa 283 Blocks in 30 districts, in Punjab all 17 districts, in Rajasthan all 32 districts, in Uttar Pradesh all 70 districts, in Uttaranchal all 30 districts, in Jharkhand all 22 districts and in Tamil Nadu 19 districts are affected by drought. Almost all States are affected by drought. What I want to say is that in 14 States all the districts are seriously affected by drought. I join myself other Members in expressing our displeasure that the Government has not done enough to tackle the situation. Somebody is telling in this House, "We are more concerned as to how to interrupt and oppose what Laluji was saying." They are concerned to oppose what Laluji has been saying. And the Government is not agreeing with us when we say that 300 starvation deaths are reported in Orissa. The Government is not at all concerned to protect the people from starvation. But the Government is more concerned to say that there are no starvation deaths either in Orissa or in any other State. I surprised and expressed my anguish and now would like to know who is primarily responsible to provide employment, food and clothing to the inhabitants of the States? The Government should be more concerned to provide water, to extend support to the farmers and also to take appropriate steps to stop the starvation deaths. Instead, the Government is using all its force to prove that there are no starvation deaths in our State. This has become the motive of the Government. I wanted to make one point clear. I would like to know who is at fault -- Central Government or the State Governments? If you look at the demands made by the States, you will know the real picture. Sir, Andhra Pradesh demanded Rs. 2,374 crores, but got only Rs. 174.61 crores; Chhattisgarh claimed Rs. 880.66 crores, but got only 92.73 crores; Haryana claimed Rs. 1,895.98 crores, got Rs. 109.65 crores; Himachal Pradesh claimed Rs. 155.86 crores, but got only Rs. 39.45 crores; Jarkhand claimed Rs. 1,447.25 crores, but got only Rs. 42 crores; Karnataka claimed Rs. 1,562.85 crores, but got Rs. 221 crores. Now, Madhya Pradesh claimed Rs.790.38 crores, but got only Rs. 125.89 crores; Maharashtra claimed Rs. 1713.61 crores, but got 20 crores; and, Orissa claimed Rs. 871 crores, but got only Rs. 120.18 crores. Now, the Government of Orissa submitted a revised claim of Rs. 1677 crores. Sir, Punjab claimed Rs. 3,529.44 crores, but got only Rs. 125.41 crores;

Rajasthan claimed Rs. 7,519.76 crores, but got Rs. 207 crores; Tamil Nadu claimed Rs. 1,545 crores, but got Rs. 228 crores; Uttaranchal claimed Rs. 401 crores, but got only Rs. 10 crores; and, Uttar Pradesh claimed Rs. 7,539 crores, but got Rs. 481 crores. So, my submission is, which assessment is correct -- State Government or the Central Government? Or, the demands of the State Governments are wrong. Or, the Central Government is not able to give money. If the State Government rightly submits its requirement, how is it that with the scanty assistance given by the Central Government the State Governments can manage such a serious situation? This is to be discussed and judged in that spirit.

Now, I will come to the situation in Orissa. We know the situation is Orissa. I represent the State of Orissa. The Below Poverty Line percentage in Orissa is the highest -- 47 per cent -- in the country. Sir, in 1999, there was a super-cyclone. In 2000, there were drought. In 2001, again, there were floods in some parts of the State and drought in other parts of the State. From 2002 till date, there are serious floods affecting all the 30 districts of Orissa. Take the case of Jajpur district, Jagatsinghpur district, Kendrapara, Cuttack, Baleshwar, Bhadrak, Korvan, Puri, Khurdard, Naigarh, Ganjam, Gajapati in coastal areas, or, take the KBK Districts, about which this Government is also making more *halla-gulla* by saying that it is giving more money to KBK Districts. Take the case of Koraput, Malkangir, Rayagada, Bolangir, Sonpur, Naupada, Kalahandi, or, the Western Districts of Orissa like Sambalpur, Bargarh, Deogarh, Dhenkanal, Sundargarh, Anugul, Keonjhar; they are also seriously affected. In Kalahandi, Naupada, Bolangir, Sonpur and Keonjhar during the last year, 300 starvation deaths were alleged. The Planning Commission enquired into it. The Human Rights Commission enquired into it. A Parliamentary Committee enquired into it. But, I am surprised that the State Government and the Central Government, instead of taking remedial measures; instead of taking appropriate steps to deal with the problem of starvation; instead of providing support to the people of Orissa; are trying to say that there have been no starvation deaths in Orissa. So, such is the situation. In Orissa, as you know,...*(Time-Bell)* Sir, I think, our party is still left with some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): No, I don't think so. There were two more Members from your party.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Okay, Sir. A Central Government Committee, which had been to Orissa, said, as reported in *The*

Orissa Dharitr, "First you spend your money, and, then, ask for more money." The hon. Minister, while replying to the discussion on drought, last time, also said, "Your Government has not spent the money." I do not know whether the Government had spent the money or not. But, now, the Government has revised the estimates, and has asked for Rs. 1677 crores. The question is: who is responsible? You are sharing power with the help of the party, which is in Government in the State, about which you are talking. The Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, does not belong to any other party, but to the party which is supporting the NDA Government at the Centre. If that Government is not spending the money, and the starvation deaths are taking place, who should be held responsible? The NDA Government, which is led by Shri Atal Bihari Vajpayee, or, anybody else in the House, or, the general public? When the money has not been spent, who should be held responsible for this negligence -- the State Government or the Central Government? Whoever may be responsible for this negligence, the people of Orissa should not be allowed to die because of the negligence of the State Government or the Central Government. Now, one more thing has been published in this newspaper, "As there have been various enquiries by various agencies, the State Government has taken a decision that the Ward Member will be held responsible if there is any starvation death in the State." What a surprise! The Chief Minister will not be held responsible, the Chief Secretary will not be held responsible, not even the Collector, not even the BDO, but the lower most elected representative of the Gram Panchayat will be held responsible, and action will be taken against him! This is the attitude of the Government. In order to avoid its responsibility, the whole responsibility has been fixed only on one man, who has no executing power. So, Sir, in such a situation, I appeal that the Central Government should take a serious view of the prevailing drought situation in Orissa and other backward States. It should be serious about the starvation deaths. And, as Mr. Gaya Singh said, if you are not going to be serious, a time will come soon when these people -- whom you are thinking are poor; whom you are thinking are weak; whom you are thinking cannot raise their protest -- will be forced to take action and you will not be able to face that. So, before the situation in Orissa acquires further serious dimensions, I, once again, appeal to the Government, through you, to take appropriate steps to improve the situation; and, also, to take appropriate steps in respect of irrigation and insurance of all the cultivated land of the country, to protect the people from drought and other natural calamities.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. The prevailing drought situation in the country is very serious. Fourteen States have very badly been affected because of it. And, the Central Government says that it has extended its financial assistance; whereas, the States say that they are not in a position to meet the challenge of drought. So far as Karnataka is concerned, 24 districts, out of 27 districts, have very badly been affected. Out of 175 Talukas, 157 Talukas are badly affected and the most affected people are farmers and rural poor. Even the cattle are also badly affected. The farmers have no say in this. There is no fodder, there are no foodgrains and there is no drinking water. These are the main problems that the people of Karnataka are facing today. The Karnataka Government has requested a financial assistance of Rs1,562.85 crores, and it had also requested for release of 11,00,095 lakh metric tonnes of foodgrains, but the Central Government has released an amount of Rs. 221/- crores only, and only 3.65 lakh metric tonnes of foodgrains have been released so far. These are quite insufficient. It does not meet the demand of the State of Karnataka. The situation prevailing there is like this. The farmers of Karnataka are committing suicides. This problem has neither been addressed by the Central Government nor by the State Government. They are freely allowing the farmers to commit suicides and they have been left to suffer. Neither the Central Government nor the State Government has come forward to provide relief to the farmers. No enquiries regarding prevailing conditions, the purchasing capacity, the fodder situation etc., have been made. This is the prevailing situation in Karnataka.

The State Governments say that we are bankrupt. Almost all the States in the country are saying that they are not in a position to pay salaries to the employees because there is no money in the Exchequer. There are no foodgrains in the State Government holding. This is the burning problem of most of the States. At the same time, the Central Government has also been saying, "we have no funds, we have no fodder. We have sufficient foodgrains, but the State Governments have not come forward, and they have not sent the requisition, that is why, we have not been able to release the food." But the ultimate sufferer is the real poor farmer and the poor coolie. They are suffering a lot.

5.00 p.m.

There is another thing which I want to mention. The situation in the State of Karnataka has become very peculiar. It has been directed that we should release water, but the fact is that we have no water. There is no drinking water in the entire State of Karnataka. The half grown crops have dried out. The farmers have lost everything. The money spent on seeds and manure has also been lost. But there is nobody to listen to us. This is the irony of the State of Karnataka. They are very respected and law-abiding citizens.

I would like to put a question to Shri Ajit Singh. I am a very small man. When I was a student, I used to listen to Shri Charan Singh. He was fighting for the cause of the farmers. He was the champion of the farmers. Unfortunately the Agriculture Minister is without the power to assist farmers. I would like to request Shri Ajit Singh, please open your mouth and convey to the Government about the serious problems being faced by the farmers. ...*(Interruptions)*...He is opening his mouth as a Minister, he is not opening his mouth as a real farmer. That is the issue. I am compelling you to say so because farmers and the poor people are facing the brunt of this. Neither the Central Government nor the State Government is coming forward to help them. What is the priority of the Government? The priority of the Government is disinvestment. Its priority is the development of the BJP in the name of Hindutva. I didn't want to say that. But, I have no objection to say that the entire attention is getting deviated from the burning problem. Under these circumstances, I would like to request the Government, particularly, the hon. Prime Minister to please try to address the problems of farmers and the drought-affected people because drought is not a one day problem. It is a continuous problem. Even after 55 years of Independence, we have not come forward with a specific policy to tackle this drought situation and how to take measures for it. Under these circumstances, if there are no funds with the State Government or the Central Government, would you allow farmers and the drought-affected people to suffer? Is it the policy of a democratically-elected Government? I urge upon the Government, 'please don't waste time. You have not released the required amount of foodgrains. For Karnataka, from February to 1st July, will be the worst period, because there will be no rain. I inquired from the Secretary of the Government of Karnataka, and he said, "foodgrains have not yet been released." Therefore, I urge upon the Central Government to release the relief funds and also the

foodgrains. Foddèr is also not available in Karnataka. You have to find a way out. If it is available in other States, arrangements should be made to transport it to Karnataka. Then, waiving of interest is also one of the important points. I know it is not exactly related to your Ministry. The farmers in Karnataka are going for loans. Bankers and lenders go to their houses and take away their utensils and other things. Therefore, I urge upon the Government to issue a directive to almost all the States in our country to suspend the recovery of loans for one year, or, till the drought situation improves. I hope the hon. Minister will interfere and do justice to the drought-affected people. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Hon. Members, there is one more speaker. Then, the hon. Minister will reply. It is already 5.00 p.m. Should we continue with the business?

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, since tomorrow we have to take up Motion of Thanks on President's Address, I would suggest, through you, to the hon. colleagues, let us complete this exercise today.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I associate with him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Then, we will continue.

SHRI R.S.GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a matter of great concern to all of us that about 14 States are facing severe drought situation. I am compelled to say that the Government of India is not taking it seriously. Remedial measures are not being taken up. I don't want to distinguish between States. Almost 14 States are faced with drought situation. The hon. Members from their respective States have given a detailed account of the situation prevailing in their State. I would also like to concentrate on Maharashtra. Maharashtra State has been facing very severe drought situation. In many districts of the State, severe drought situatiion has been existing for the last three years. During the last two years, Central teams visited the State of Maharashtra to observe the drought situation. The Committees were acclimatised with the drought-affected areas to the extent possible. Also, detailed information was supplied to the Committees. Discussions were held among the Secretaries and Commissioners at various levels. Unfortunately, the Ministry of Agriculture has informed that according to the findings of the Central Team, there is no serious drought condition in the State of Maharashtra except moderate degree of drought condition in isolated pockets. This is totally

untrue. The further observation of the Committee is that the State Government is seeking to finance mainly the Employment Gurarantee Schemes through CRAF/NCCF, which is not permissible. This is also not true and baseless. As a matter of fact, Maharashtra State was a pioneer State to start an Employment Guarantee Scheme. I was fortunate enough to associate myself with the Scheme along with the then Chief Minister, Shri V.P. Naik, the then Chairman of the State Council, Shri Page. I was the Deputy Chairman of the Maharashtra Legislative Council. Under this Scheme, a job is guaranteed to an agriculture labour, where agricultural situation is not good. This scheme has been in existence since 1972. By adopting an enactment, the Employment Guarantee Scheme was passed by the Legislature unanimously. Today, it is an ideal scheme for the whole nation. The Government of India through the Employment Assurance Programme is providing employment for some days, not permanently; it is not a guarantee. But the Government of Maharashtra is spending huge amount for the last 35 years, and thereby providing gainful jobs to the agricultural labourers and creating productive works throughout the State. The observation of the Committee that the State Government is seeking to finance its Employment Guarantee Scheme is totally baseless. I would like to point out this fact.

Sir, during the last three years because of erratic rains and a long dry season, both the Kharif and Rabi crops were badly affected in Maharashtra. Maharashtra is facing severe shortage of drinking water in most of the districts. During the year 2000-01, drought was declared in 23,954 villages in 26 districts; in the year 2001-02, in 7,497 villages in 16 districts; and, this year the scarcity situation exists in 33 districts. Keeping in view the situation which I exhibit, I request, on behalf of the Maharashtra Government, for providing a special assistance of Rs. 1,000 crore from the NCCF to enable it to tackle the severe drought condition such as supply of drinking water and generation of employment. The Central Government has so far sanctioned only Rs. 20 crore as against a demand of Rs. 1730.61 crore by the State Government. This also indicates that an injustice is being done towards the Maharashtra State. As per the figures revealed by the various States about their demand and amount approved by the Central Government to the concerned respective States, I humbly want to bring this anomaly to the notice of the Central Government, and further request the Central Government to apply the same logic and rationale to the Maharashtra State, as it has applied to the other States, which are facing the drought condition.

SHRI LALITBHAI MEHTA: Sir, before the hon. Minister replies, I want to make one point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Let the Minister reply first. After that, you can speak. Yes; Mr. Minister.

श्री अजित सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज इस सत्र के शुरुआत में हम यहां सूखे पर बहस कर रहे हैं । हमने पहले भी सूखे पर कई बार बहस की है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले साल का सूखा, हमारे देश के इतिहास में काफी चिंताजनक व भयंकर सूखा पड़ा था और अब इस रबी में भी सूखे का क्या असर है यह सभी सदस्यगण जानना चाहते हैं और पिछले साल के सूखे का क्या असर रहा और सरकार ने क्या मदद की वे यह भी जानना चाहते हैं । कुछ लोगों ने चिंता प्रकट की है कि राज्यों के साथ हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। राघवन साहब ने चिंता प्रकट की है कि यदि राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है तो हम क्यों नहीं कुछ करते । लालू प्रसाद जी से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि और चीज़ों की चिंता तो उन्होंने की ही, लेकिन सूखे में कंबल की मांग भी उन्होंने की है और यह भी आशंका जाहिर की है कि वे कुछ कहेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। लेकिन वह यह नहीं जानते कि उनसे तो मेरे बड़े पुराने संबंध हैं और वह कुछ भी कहें, मैं नाराज़ होने वाला नहीं हूं ।

श्री लालू प्रसाद : तब तो ठीक है ।

श्री अजित सिंह : बल्कि अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि लालू जी के कहने से कोई भी नाराज़ नहीं होता । इनके सहयोगी दल और नए-नए सहयोगी दल, बल्कि अब तो कांग्रेसी भी ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद : हम इनको धन्यवाद देते हैं और अब हम जा रहे हैं ।

श्री अजित सिंह : अब तो कांग्रेसी लोग भी हंसते हैं और नाराज़ नहीं होते हैं । इसलिए यह चिंता की बात नहीं थी । मुझे आपको आंकड़ों को बताने की जरूरत नहीं है । यह सही बात है कि सूखा पड़ा है । जो रबी अब आ रही है इसमें जो हमारे पास खबरें हैं उसके अनुसार चार राज्यों में रबी की फसल पर सूखे का असर पड़ा है । उसमें मध्य प्रदेश में बुवाई 18 प्रतिशत कम हुई है, राजस्थान में 53 प्रतिशत कम हुई है, तमिलनाडु में 24 प्रतिशत कम हुई है और गुजरात में 26 प्रतिशत कम हुई है । वहां हमने टीम्स भेजी हैं और उनकी रिपोर्ट आ रही है । अभी तक जो सहायता दी गई है वह 31 जनवरी तक थी । अब सूखे पर जो नई टीम्स की रिपोर्ट्स आयेंगी उनके आधार पर तय किया जाएगा कि कितनी मदद दें । यह भी माननीय सदस्यों को मालूम है, लेकिन फिर से बताना चाहूंगा कि क्या परिस्थिति है, रबी की क्रॉप के बारे में क्या एस्टीमेट्स हैं और खरीफ के बारे में हमारे फाइनली क्या एस्टीमेट्स हैं और कितना नुकसान हुआ है । यह पहली बार हमारे देश में हो रहा है और 12-15 साल के बीच में एक बार पहले भी हुआ है कि रबी की फसल, जहां तक खाद्यान्नों का सवाल है, वह खरीफ से ज्यादा होगी । वरना हमेशा खरीफ का योगदान हमारे खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा रहा है । इस से पता चल जाता है कि इस बार खरीफ फसल में काफी नुकसान हुआ है ।

जहां तक फूड ग्रेंस का सवाल है, अनुमान है कि रबी और खरीफ दोनों मिलाकर करीब 13 प्रतिशत कमी इस बार उत्पादन में होगी । जो हमारे सपोर्ट सीरियल्स हैं, उस में 26

प्रतिशत की कमी होने की आशंका है । यह रबी और खरीफ दोनों मिलाकर है । पल्सेस में 13 प्रतिशत कमी है और ओइल सीड्स में 25 प्रतिशत के करीब कमी है । इस तरह कमी सभी चीजों में है । कॉटन मे 11 प्रतिशत कमी होगी, जूट में एक प्रतिशत कमी होगी, शुगरकेन करीब 5 प्रतिशत कम होगा । तो सूखा खरीफ हो या रबी हो, दोनों के लिए काफी भयंकर रहा है और इस बार हमारे ग्रामीण इलाकों मे चाहे किसान हो या मजदूर हो, उन के लिए समस्या काफी गंभीर रही है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आरोप लगाए गए हैं कि हम भेदभाव करते हैं । आंध्र प्रदेश के प्रति सभी सदस्यों की यह भावना रहती है क्योंकि हमारी सहयोगी पार्टियों में वह सब से बड़ी पार्टी है । इसलिए सब से ज्यादा हम आंध्र प्रदेश को देते हैं । मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश को टोटल असिस्टेंस कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड से 14 करोड़ से कम दिया गया है । छत्तीसगढ़ जोकि बहुत छोटा स्टेट है उसे 81 करोड़ से ज्यादा दिया गया है, मध्य प्रदेश को 132 करोड़ के करीब दिया गया है और कर्नाटक को करीब-करीब 190 करोड़ दिया गया है, तमिलनाडु को 133 करोड़ दिया गया है । तो यह कहना गलत होगा कि जहां पर सरकार का जो राजनीतिक स्वरूप है, उस तरह से मदद दी जा रही है ।

श्री एन0के0 प्रेमचन्द्रन (केरल): केरल को क्या दिया गया है ?

श्री अजित सिंह : सर, केरल की समस्याओं में फर्क है । इस तरह मैं सभी प्रदेशों का कह सकता हूं ।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): What about Pondicherry?

श्री अजित सिंह : पांडिचेरी को सूखे के बारे में कोई मदद नहीं दी गयी है ।

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): गुजरात ने सूखे की समस्या का मेमोरेंडम अब भेजा है । वहां टीम गयी है । यहां पिछले सूखे के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी ।

श्री प्रणब मुखर्जी : राजस्थान का फिगर बताइए ।

श्री अजित सिंह : राजस्थान को 167 करोड़ दिया गया है । इस में से ज्यादातर पैसा जो 2 हैक्टेयर तक की रिलीफ सब को देने की बाद में पधान मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस मद में से आया है ।

श्री सुरेश पचौरी : उन राज्यों की मांग कितनी थी ?

श्री अजित सिंह : मैं आप को मांग भी बता दूंगा ।

डा0 अबरार अहमद (राजस्थान): सर, इस में एक बात और महत्वपूर्ण है । आप ने जिस योजना के तहत यह पैसा दिया है, उस में 625 करोड़ की आवश्यकता है और आप ने सिर्फ यह राशि दी है, आप इसे प्रपोर्शनेटली बांट नहीं सकते तो वह पैसा भी बेकार पड़ा हुआ है।

श्री अजित सिंह : सर, 17 राज्यों की करीब-करीब 35 हजार करोड़ की मांग थी । इस में एन0सी0सी0एफ0 से करीब 2 हजार करोड़ रिलीज किया गया था। बाद में यह 2 हैक्टेयर

के लिए करीब 365 करोड़ और रिलीज किया गया है । अब जो मांग की जाती है, कुछ सदस्यों ने ...(व्यवधान)..

डा0 अबरार अहमद: सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो राशि आप ने दी है और जिस योजना में दी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Let him complete, and then put questions. ....*(Interruptions)* .....

डा0 अबरार अहमद : उस को प्रपोर्शनेटली नहीं कर सकते । जो भी 2 हजार हैक्टेयर से कम वाले हैं, उन को दें तो सभी को दें । उस हिसाब से 625 करोड़ की आवश्यकता है । अब उस 170 करोड़ को कैसे बांटें, क्या इस बारे में कोई तरीका सुझाया है । आप एक-चौथाई को दे दें और तीन-चौथाई को छोड़ दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Let him complete.

श्री अजित सिंह: यह क्वेश्चन-आंसर सेशन नहीं है । अभी आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उन का जवाब देने की कोशिश करूंगा और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आप का सवाल रह जाय तो आप कभी भी मुझ से बात कर सकते हैं । मैं जो भी आंकड़े हैं, वह आप को दे दूंगा । सर, यह जो 35 हजार करोड़ की मांग की गयी है, उस में जो पैसा हम कंटिंजेंसी फंड से दे सकते हैं या कैलेमिटी रिलीफ फंड से किस मद में पैसा खर्च किया जा सकता है, यह ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन ने तय किया है । उस के लिए उन्होंने मापदण्ड बनाए हैं । वह मापदण्ड मुख्य मंत्रियों की सहमति से बने हैं । अब यह जो 35 हजार करोड़ की मांग है, उस में बहुत सी जगह सिंचाई के लिए जरूरत है, सड़क बनाने के लिए जरूरत है, पुल बाढ़ मे बह गया था उस के लिए जरूरत है, कम्बल के लिए जरूरत है । यह सब जो ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन ने कैलेमिटी फंड और कंटिंजेंसी फंड के लिए मापदण्ड बनाए हैं, उस के बाहर है । जो आफीसर यहां से जाते हैं, वे प्रदेश सरकार जो उनको कहती है उस पर डाऊट नहीं करते । यहां से जो सरकारी आफीसर जाते हैं, वे सिर्फ दो तीन जगहों पर जाकर ही बात कर सकते हैं, सब जगह नहीं जा सकते हैं । हमको सरकार जो आंकड़ें देती हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन वह आंकड़ें या उनकी मांग इस मापदंड के अंदर आती है या नही आती है, यही सरकारी आफीसर तय करते हैं । यहां के आफीसर वहां जाकर यह तय नहीं करते कि आपके यहां कितनी जगह बाढ़ आई है या सूखा पड़ा है, कितने गांव में असर पड़ा है या कितनी तहसीलों में असर पड़ा है । यह तो हम प्रदेश सरकार के आंकड़ों को ही मानते हैं, लेकिन जो मांग की गई है वह मांग इस मापदंड के अंदर है या नही, यह सवाल उसमें उठता है और इसलिए यह पैसे की कमी है, बहुत सी स्टेट में है ।

महोदय, जैसा राजस्थान वालों ने सवाल उठाया है, हमने कहा कि 167 करोड़ रुपए दिए हैं । ऐसा नहीं है कि उनको खाली 167 करोड़ रुपया ही एलाट हुआ है । उनके पास 217 करोड़ रुपया कैलेमिटी रिलीफ फंड में 31अक्तूबर तक बेलेन्स में था, जो उनके आंकड़े हैं और इस आधार पर यह पैसा दिया गया है । जब वह हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे कि उन्होंने यह पैसा खर्च कर दिया है । ...(व्यवधान)... अभी हमने राज्यों से बात की है । पैसे की

कमी अब कोई नहीं मान रहा है । अप्रैल में इस साल का कैलेमिटी रिलीफ फंड आपको और मिलने वाला है और राजस्थान के लिए हम एडवांस रिलीज कर रहे हैं उसका 50 परसेंट ।

डा0 अबरार अहमद : माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी प्रोब्लम राजस्थान में यह है कि यह जो कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा आप वहां रिजर्व मान रहे हैं, वह वहां नहीं है । वहां पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा था ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Dr. Abrar Ahmed, don't disturb the Minister. Let him complete. After that, I will give you a chance.

डा0 अबरार अहमद : महोदय, यह तकनीकी बात है, जैसा माननीय मंत्री जी कहते हैं । अब वहां तीन साल से लगातार अकाल है, जिससे कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा बचा हुआ नहीं है और आप उसे मानकर लगातार यह बात कहे जा रहे हैं । इससे राजस्थान की समस्या और एक्यूट हो रही है. । जो दूसरे पैसे की बात कही है, वह आप मेरी बात को समझे नहीं । माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने दो हैक्टेयर से कम वाले के लिए पैसा दिया है 167 करोड़ रुपया, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी वहां के मुख्य मंत्री जी ने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और बताया था कि दो हैक्टेयर वालों को देने के लिए 625 करोड़ रुपया चाहिए । तो वह यह 167 करोड़ रुपया किस-किस को दें ? क्या एक चौथाई को दें, तीन चौथाई को छोड़ दें । तकनीकी बात है और वह पैसा भी पड़ा हुआ है ।

श्री अजित सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, इसमें एक तो सवाल यह है कि क्या हम यह कर सकते हैं कि अगर हमको प्रदेश सरकार ने खबर नहीं भेजी कि उन्होंने पैसा खर्च कर लिया है और उसके बावजूद हम रिलीज कर दें ? कल फिर माननीय सदस्य इस सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे । फिर सीएजी भी उसको चैक करती है । इसलिए जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा तब तक हम और पैसा देने में असमर्थ हैं । यह हमारे हाथ में नहीं है । फिर सीएजी भी चैक करती है । यह नार्म्स बनाए हुए हैं ।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Dr. Abrar Ahmed, don't interrupt the Minister.

श्री अजित सिंह : अब आप देखिए । आपने सवाल उठाया । स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए राजस्थान को 107 करोड़ रुपया इनपुट सबसिडी दी गई और 165 करोड़ रुपया दो हैक्टेयर तक के बड़े फार्मर्स के लिए दी गई । ...(**व्यवधान**)...

डा0 अबरार अहमद : वह बेकार पड़ा हुआ है ।

श्री अजित सिंह : 107 करोड़ रुपया दो हैक्टेयर से नीचे को। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER ONF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, if the hon. Member continues like this, it will lead to a further debate.

श्री अजित सिंह: महोदय, 272 करोड़ रुपया फार्मर्स को बांटने के लिए जो इनपुट सबसिडी राजस्थान को दी गई, जो राजस्थान के आंकड़े हैं उसी के आधार पर इनको दी गई। इसमें से रिलीज जितनी हुई है वह जैसा मैंने आपको बताया 167 करोड़ रुपए की क्योंकि बाकी पैसा आपके कैलेमिटी रिलीफ फंड में है वरना 272 करोड़ रुपया राजस्थान में फार्मर्स को बांटने के लिए दिया गया है।

महोदय, अब ओवरऑल असिस्टेंस की बात है कि कितनी दी गई। इस साल कैलेमिटी रिलीफ फंड से करीब 1400 करोड़ दिया गया है, कंटिनजेन्सी फंड से करीब करीब 1100 सौ करोड़ दिया गया है, जो फूडग्रेन ऑलरेडी हम दे चुके हैं उससे 3000 करोड़ करीब उसका खर्चा है। वाटर सप्लाई के लिए 3500 करोड़ रुपया दिया गया है, जानवरों के लिए और खासतौर से जो राजस्थान में है, पशुओं के लिए 50 करोड़ रुपया दिया गया है और रेलवे जो फ्री फोडर का ट्रांसपोर्ट कर रही है और गुजरात के लिए भी हमने एलाऊ कर दिया है उसके लिए भी 25 करोड़ दिया जा चुका है। टोटल 5575 करोड़ रुपया एस्टीमेटेड दिया जा चुका है।

महोदय, जो एक मांग माननीय सदस्य ने उठाई थी, राजस्थान ने भी उठाई थी कि हम प्लान कर लें आगे के लिए कि किस तरह फूडग्रेन रिलीज करें, वह किया जा चुका है और राजस्थान को हम 20 लाख टन जुलाई के आखिर तक और खाद्यान रिलीज करने वाले हैं। हर महीने कितना रिलीज होगा, वह बात हो रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि राजस्थान के सदस्यों की, बल्कि इस सदन के सभी सदस्यों की जो चिंता है राजस्थान के सूखे के बारे में, वह वाजिब है। राजस्थान में सूखा सबसे भयंकर पड़ा है और राजस्थान में पांच किलोग्राम प्रतिदिन फूड फार वर्क के लिए दिया जाता है और वह बी0पी0एल0 से 20 प्रतिशत फैमिलीज़ को दिया जाता है। राजस्थान में हमने फिर से स्टडी कराई है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूखा भयंकर है, वहां 94 ब्लॉक्स में हरेक फैमिली को फूड फार वर्क के लिए फूड दिया जा रहा है और 6 किलोग्राम दिया जा रहा है। बाकी ब्लॉक्स में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को फूड फार वर्क के लिए खाद्यान्न हम दे रहे हैं और वहां भी 6 किलोग्राम प्रतिदिन दे रहे हैं। तो राजस्थान की समस्या को समझते हुए केन्द्रीय सरकार जितनी मदद कर सकती है, और राज्यों के मुकाबले वह राजस्थान की ज्यादा ही मदद कर रही है, कम मदद करने का तो सवाल ही नहीं है और जो राजस्थान ने किया है वह आपको अच्छी तरह से मालूम है। वहां समस्याएं हैं, रेलवे का भी मूवमेंट है, वहां के केटल फीड के लिए हमने 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं भी रिलीज़ किया है। इसलिए मदद करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं।

कुछ और सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, उनका भी मैं अलग से जवाब देना चाहूंगा। लॉंग टर्म का मैंने कह दिया, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने बताया है। गौड़ा साहब ने मांग उठाई थी कि जो लोन्स की रिकवरी है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि पांच साल के लिए लोन्स रिशेड्यूल्ड किए जा चुके हैं, आर0बी0आई0 इंस्ट्रक्शंस भेज चुकी है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: We are only taking care of the interest part.

श्री अजित सिंह : गौड़ा साहब ने अभी यह मांग की थी कि लोन्स की रिकवरी रोक दी जाए एक-दो साल के लिए। तो लोन्स चार और पांच साल के लिए रिशेडयूल्ड कर दिए गए हैं

और उस रिशेडयूल में एक साल का ब्याज भी माफ कर दिया गया है । मैं यह मानता हूं कि समस्या बड़ी गंभीर है, बहुत मदद की जरूरत है । पहली बार 11वें फाइनेंस कमीशन ने रेगुलरली आपदाओं के लिए प्रदेशों को पैसा देने का काम किया है । 1997 से यह शुरु हुआ है, पहले उसे पैसा केन्द्रीय सरकार नहीं देती थी । 1987 में जितना खर्चा किया गया केन्द्रीय सरकार द्वारा, उससे कहीं ज्यादा खर्चा इस साल सरकार कर चुकी है । इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा कि 11वें फाइनेंस कमीशन ने यह मानते हुए कि देश के किसी न किसी कोने में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं तूफान, इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, इसलिए नेशनल केलामिटी रिलीफ फंड से हर साल राज्यों को पैसा दिया जाता है और वह पैसा ऐक्यूमलेट होता रहता है । अगर उस राज्य में कोई आपदा नहीं आती तो फिर तीन या पांच साल, शायद तीन साल तक वह पैसा ऐक्यूमलेट होता रहता है । इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ राज्यों के पास उसका बैलेंस है । यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उपसभाध्यक्ष जी, कि बहुत से प्रदेशों में वह सही खर्च नहीं हुआ । वह पैसा कहां गया, किताबों में तो है पर वह कहां खर्च हुआ, इसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं और न आप लोग चाहेंगे कि मैं राज्यों के बारे में, किसी राज्य के बारे में कहूं कि उन्होंने पैसा डाइवर्ट किया या नहीं किया ।...**(व्यवधान)**...यह हमारा प्रजातंत्र है, फेडरल सिस्टम है, यह डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड सरकारें हैं और अगर कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है कि सूखे के उस पैसे को उन्होंने ठीक से खर्च नहीं किया है तो वहां की जनता को जल्दी ही मौका मिलने वाला है, वह उनको बतला देगी कि उस सरकार ने ठीक काम किया है या नहीं किया है, लेकिन यह केन्द्रीय सरकार का काम नहीं है कि हम मॉनिटरिंग करें । यह ठीक है कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं बहुत सी स्कीम्स में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में हम कुछ कदम उठा रहे हैं कि जो पैसा दिया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए । बल्कि हम तो यह कदम उठा रहे हैं कि मॉनिटरिंग केन्द्रीय सरकार या सरकारी एजेंसी से न कराएं, बहुत सी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनसे कराएं । जैसे हमने उत्तर प्रदेश में अभी चलाया है, वहां पर इंडियन इंस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट है, हम उनको ही काम देना चाहते हैं कि वह मॉनिटरिंग करे और बताए कि जो हमने पैसा दिया है, सरकार वह योजना किस तरह चला रही है । लेकिन केन्द्रीय सरकार यह तय करे कि कोई प्रदेश सरकार खर्चा सही कर रही है, नहीं कर रही है या पैसा कहां जा रहा है, यह हम नहीं चाहते । इंडिविजुअल स्कीम्स हम मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन यह प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है और खास तौर पर खेती तो प्रदेश सरकार के अंदर ही आता है । हम तो सिर्फ योजना ही बना सकते हैं और पैसा देने का काम ही कर सकते हैं लेकिन यह सही बात है कि इस साल जो कमी हुई और जैसे मैंने अभी आंकड़े दिए, हरेक फसल में कमी हुई और आयल सीड्स मे, करीब 25 प्रतिशत कमी है खाद्यान्नों में । यह तो हमारे लिए किसानों को बधाई देने की बात है कि इस सिवियर ड्राउट के बावजूद उन्होंने इतना खाद्यान्न पैदा किया है कि हम अपने लोगों को खिला सकते हैं, उसे बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है । कोई बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है । लॉग-टर्म मैजर्स के बारे मे लोगों ने कहा है । यह ठीक है कि अभी हमारे देश में खाली 37 प्रतिशत जमीन सिंचित है और यह भी बढ़ी है, पहले इतनी जमीन सिंचित नहीं थी और जो रेन-फैड ऐरियाज़ हैं, वहां भी बहुत सी स्कीम्स सरकार चला रही है । पानी की कमी हमारे देश में होने वाली है । एक योजना नदियों को जोड़ने की है, कुछ लोग नाराज़ थे कि इसमें दस साल लगेंगे या चालीस साल लगेंगे । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितना पैसा उसमें लगेगा क्योंकि अभी तो स्टडी हो रही है कि वह फीज़ेबल है या नहीं और उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कौन सी नदियां जोड़ी जाएंगी, यह बाद की बात है । जब

पंजाब, हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं है, जब कर्नाटक, तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार नहीं है ...(व्यवधान)...मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे किसी दुर्भावना से पानी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि कर्नाटक में समस्या हो लेकिन फैक्ट यह है कि वे पानी नहीं दे रहे हैं । हो सकता है कि उनके पास पानी न हो । तो यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम किस तरह से नदियों को जोड़कर पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं । इस बारे में हमने एक कमेटी बनाई है लेकिन सच्चाई यह है कि पानी की समस्या हमारे देश में आने वाली है। खाली नदियों को जोड़ने की नहीं, वॉटर कंजरवेशन की और भी बहुत सी योजनाएं हैं, हमारे जो परंपरागत तरीके हैं, उनको आगे बढ़ाने की योजनाएं हैं । इस सूखे पर आप लोगों ने जो चिंता ज़ाहिर की है, वह स्वाभाविक है क्योंकि हमारी 66 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है और इस साल काफी भयंकर सूखा पड़ा है लेकिन अभी तक रबी में सिर्फ चार राज्यों में सूखे के असर की रिपोर्ट है । वहां टीमें भेजी गई हैं और जो भी मदद हम कर सकते हैं, वह हम करेंगे ।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, what about the assurance given relating to Kerala? The drought is adversely affecting the cash crops. The State Government has requested to waive off the loans. What is your response?

श्री अजित सिंह : केरल में 100 करोड़ रुपए का बैलेंस कैलेमिटी रिलीफ फंड में है ।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, the problem is, the cash crop farmers who have been adversely affected, are not getting any benefit. You have to relook into the matter concerning the loans meant for cash crops farmers.

श्री अजित सिंह : राघवन साहब, समस्याएं बहुत हैं, आपके राज्य में भी हैं और दूसरे राज्यों में भी हैं । अलग-अलग राज्यों में किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं । आपके यहां कोकोनट के प्लांटेशंस बहुत पुराने हो गए हैं, शायद उनको रिन्यू करने की जरूरत है, वह स्कीम भी आपने हमें भेजी है और हम उसके बारे में प्लानिंग कमीशन से बात कर रहे हैं । तो हरेक राज्य में, हरेक क्षेत्र में किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं । गन्ना किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं । महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इस बार गन्ना किसानों के सामने भयंकर समस्या है ...(व्यवधान)...

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: You, please, relook into the issue.

श्री अजित सिंह : लेकिन अगर आज आप किसानों की समस्याओं पर बहस करना चाहते हैं तो करिए, अगर पूरे सैशन में भी आप बहस करें तो शायद आप पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे।

महोदय, आज सूखे के मामले पर सरकार क्या कर सकती है, क्या किया है और आपकी जो चिंता है, इस पर यहां बहस हुई । आपसे भी कुछ जानकारी हमें मिली और मेरे पास जो आंकड़े थे, वे आंकड़े मैंने दिए हैं । हम इस बारे में जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम जरूर करेंगे ।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के उप-सचिव श्री नेगी का 9 जनवरी, 2003 का पत्र मेरे सामने है जो उन्होंने विभिन्न सूखा प्रभावित राज्यों को भेजा था जिसमें उन्होंने यह कहा है कि -

"The Task Force on Drought has now decided that allocations will be made to your State so as to cover 75 per cent of BPL rural households, based on the requirements of 5 kgs. per day, per household, for ten days every month, till June, 2003."

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले जो ऐलोकेशन था, वह 10 किलोग्राम था जिसे घटाकर अब 5 किलोग्राम कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि यह जो मजदूरी का समय दिया गया है, वह 10 दिन दिया गया है । एक माह में 10 दिन कार्य करना कृषि मंत्रालय ने आवश्यक समझा है । जब मैंने अपनी बात आरंभ की थी, तब भी मैंने यह कहा था कि सामान्यत: जो कृषि से संबंधित परिवार हैं, उनके यहां पांच या छह या आठ सदस्य होते हैं, इतने सदस्यों वाले परिवार में जो सूखा पीड़ित परिवार है, उसकी समस्या को देखते हुए यदि आप इसे बढ़ाकर पंद्रह दिन कर दें तो मैं सोचता हूं कि इससे उनको राहत मिलेगी। आखिरी बात यह है कि आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों का जिक्र किया है । पहली बात तो यह है कि उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी जो पैसा या फूडग्रेन्स गए हैं, उसके 80 प्रतिशत यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट उन्होंने आपको भेज दिया है । अभी 17 तारीख को ही छत्तीस गढ़ के मुख्य मंत्री ने आपको पत्र लिखा है और प्रधान मंत्री जी को उसकी कॉपी दी है जिसमें उन्होने कहा है कि वह 80 प्रतिशत व्यय कर चुके हैं। छत्तीस गढ़ ने मांग 880 करोड़ की थी और 81 करोड़ दिया। मध्य प्रदेश ने 315 करोड़ की मांग की आपने 132 करोड़ दिया। यह भेदभाव दर्शाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद, आप मेहरबानी करके सूखे को बेरॉमीटर मानते हुए राहत राशि दें तो कृपा रहेगी।

श्री अजित सिंह : कितना मांगा और कितना दिया, अगर यह देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ने 1200 करोड़ मांगा था और उनको 13 करोड़ दिया गया है। तो जितना मांगा था वह बात नहीं है। जहां तक राजस्थान का आपने सवाल उठाया, राजस्थान में सूखा ज्यादा भयंकर है इसलिए पिछली मीटिंग में टॉस्क फोर्स ने तय किया था कि उनके लिए अलग स्टडी करनी है। पिछले हफ्ते टॉस्क फोर्स की जो मीटिंग 13 तारीख को हुई थी उसमें राजस्थान के लिए हमने 97 ब्लौक्स में 100 परसेंट फेमिलीज को कवर किया है ए0पी0एल और बी0पी0एल0 बोथ में।......(व्यवधान) 8 किलोग्राम और 6 किलोग्राम राजस्थान के लिए है, कहीं 10 किलोग्राम नहीं था। 5 किलोग्राम ही यह देश में रहा है हमेशा। राजस्थान को तो हमने बढ़ा कर 8 और 6 किलोग्राम कर दिया है। उपसभाध्यक्ष जी, एक और बात है। यह जो हम फूडग्रेन दे रहे हैं यह एस0जी0आर0वाई0 में जो एलोकेशन है उसके अलावा है। यह नहीं है कि इतना ही फूडग्रेन हम सब स्टेट्स को दे रहे हैं। एस0जी0आर0वाई0 में और भी बहुत से फूडग्रेन स्टेट्स के पास हैं।

श्री सुरेश पचौरी : दस दिन कार्य करने का जो मापदंड है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Mr. Manoj Bhattacharya, please try to be very brief.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact, I have referred to it in my earlier speech also, that on 9th of August, he has stated that Andhra Pradesh had scanty rains in 4 districts and deficient rains in 15 districts; Madhya Pradesh had scanty rains in 30 districts and deficient rains in 12 districts; Rajasthan had scanty rains in 27 districts and deficient rains in 5 districts; and Uttar Pradesh had scanty rains in 45 districts and deficient rains in 17 districts. The Central allocation from the Calamity Relief Fund, as replied by you only, was Rs. 81.89 crores for Andhra Pradesh, Rs. 25.89 crores for Madhya Pradesh and Rs. 85.58 crores for Rajasthan. So, my question is, whether this allocation has been done in conformity with the damage that has occurred, because of drought. What is the criterion you have followed? I must know that. I am not going to talk about discrimination. But, here, from the replies of yours, I am literally confused that there is a discrimination. There is no parity between the extent of damage, as reported by you, and the amount of money allocated by you. This is number one. My second question, Sir, is ....*(Interruptions)*.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Sir, he did not mention with regard to Kerala. ....*(Interruptions)*. We have given a ....*(Interruptions)*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the Minister has said ....*(Interruptions)*.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, my second question is....*(Interruptions)*. Whether this National Fund for ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): No second question please.

SHRI AJIT SINGH: I would like to invite hon. Members -- who have some questions about how much money spent, how much money released, how much was asked, what are the parameters, how it is decided, etc. -- to my chamber and will be very happy to discuss with them individually.

श्री ललितभाई मेहता : माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी ने पिछले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यह घोषणा की थी कि 25 करोड़ अकालग्रस्त विस्तार के राज्यों के पशुओं के लिए वह अलग से देंगे। इसके लिए एक कमेटी बननी थी। कमेटी में आपके मंत्रालय का एक अधिकारी और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का तथा...**(व्यवधान)**...

श्री अजित सिंह : यह बन गई है और देना शुरू कर दिया है।

श्री ललितभाई मेहता : लेकिन बात यह है कि जो कमेटी बनी है वह कमेटी सभी राज्यों से मंगा रही है। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि एक हजार से ज्यादा पशु जिस गौशाला में हैं उसको सीधी ही सहायता केन्द्र सरकार देगी। वह जो नॉर्म बनाया गया है वह सभी राज्य सरकारों को भेज रहे हैं। राज्य सरकार के सचिव कलेक्टर को भेज रहे हैं, कलेक्टर मामलतदार को भेज रहे हैं, मामलतदार तलाटी को भेज रहे हैं। इसमें बहुत समय लग रहा है। पशुओं के लिए धन की आवश्यकता जल्दी से है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह कार्य शीघ्र से शीघ्र हो सके, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं?

श्री अजित सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर मेहता जी सर्टीफाई कर दें कि इस गौशाला में इतने पशु हैं तो हमारी कमेटी जरूर मान जायेगी। लेकिन कहीं न कहीं तो चैक करना पड़ेगा कि उस गौशाला में कितने पशु हैं। अब प्रदेश सरकार उसको कैसे सर्टीफाई करती है, यह उनके हाथ में है। धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): The House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 20th February, 2003.

MGIPMRND—8328 RS—20-11-2003.